we saw to it that all our Jumbo aircraft went in for a thorough check-up and only two aircraft had little dents within the limits of the safety certified by the Boeing Company. We did this check-up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2-30 p.m.

The House then adjourned for lunch at twenty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled, after lunch, at thirty-two minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman in the Chair.**

MESSAGES FROM LOK SABHA— *contd.*

(I) The Appropriation (Railways) Bill, 1986

(II) The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1986

(III) The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1986

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

I

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) Bill, 1986, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 13th March. 1986.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

II

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1986, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 13th March, 1986.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

III

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1986, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 13th March, 1986.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

RESOLUTION REGARDING APPOINTMENT OF A COMMISSION TO INQUIRE INTO THE BACKWARDNESS OF EASTERN UTTAR PRADESH— *contd.*

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं उस रोज यह कह रहा था कि कल्पनाथ राय जी का जो प्रस्ताव पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये है, उसमें जगदम्बी प्रसाद यादव जी ने थोड़ा संशोधन कर दिया और उसको बिहार तक बढ़ा दिया और फिर हमारे और माननीय सदस्यों ने उसको देश के हर अविकसित क्षेत्र से जोड़ दिया, सातवीं पंचवर्षीय योजना से जोड़ दिया, इससे यह प्रस्ताव व्यापक बन गया है। मैं उस व्यापक प्रस्ताव पर आज नहीं जाना चाहता

[श्री रामचन्द्र विकल]

परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, उनका विकास हो, इसके लिए मैं कल्पनाथ राय जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभापति महोदय, जो हमारी योजना बन रही है वह इस ख्याल से बनाई जाय कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश के जो अविकसित भाग हैं, विशेषकर उनको प्राथमिकता दी जाय। सिंचाई के मामले में, सड़कों के मामले में, स्कूलों के मामले में, अस्पतालों के मामले में और विशेषकर उद्योग-धंधों के मामले में प्राथमिकता दी जाय। जहां तक उद्योग धंधों का सवाल है, यह देखा जा रहा है और हो रहा है कि उद्योग पति दिल्ली में रहकर सारे उद्योग धंधे दिल्ली के आसपास ही खोलना चाहते हैं। मेरा क्षेत्र सिकन्दराबाद और दादरी में है। मैंने इंदिरा जी को भी एक बार कहा था कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं हिन्दुस्तान के, वहां पर इंडस्ट्रीज खोली जाय। लेकिन हो यह रहा है कि दिल्ली के आसपास सारे उद्योग लाये जा रहे हैं। उद्योगपति अपने दफ्तर यहीं रखकर दिल्ली के आसपास अपना उद्योग लाना चाहते हैं और इसके लिए जमीन एक्वायर की जा रही है। जो अविकसित क्षेत्र हैं देश भर के और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, अगर वहां पर हर जिले में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री खोली जाय तो उस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। एक इंडस्ट्री लगने से उस इलाके के बहुत से लोगों को रोजी मिलती है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मजदूर भाई, लेबर, जो दिल्ली में आकर अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं उनको वहीं रोजगार मिल जाता है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाके में आप इंडस्ट्री खोलते हैं तो वहां 10-10 मील से व्यक्ति साइकल पर चलकर कारखाने में नौकरी कर सकता है। यहां सारे हिन्दुस्तान में लोग दिल्ली में जमा होते हैं। फिर यहां झुग्गी झोंपड़ी का सवाल, आए दिन बीमारियों का सवाल, अपराधों का सवाल भी इन्हीं के कारण बढ़ता है। जो लोग बेकार हो जाते हैं वह कोई न कोई अपराध करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इंडस्ट्रीज को अधिक से अधिक फैलाया जाए। दूसरा यह कि सिंचाई के साधन भी किसान को दिये जाएं। इस देश का किसान मेहनत करना चाहता है। लेकिन उसको सिंचाई के साधन दिये जाने चाहियें। जहां तक मैं देखता हूं हर राज्य में किसान को दी जाने वाली बिजली के घंटे बांध दिये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान अव्वल तो बिजली की दरें इतनी ज्यादा हैं कि अनावश्यक बिजली जलाना नहीं चाहता है। वह तभी बिजली का इस्तेमाल करता है जब उसको फसल को पानी देना होता है। बिना वजह और बिना जरूरत के किसान फसल को रोज रोज पानी नहीं देता है। किसान पर बिजली की पाबन्दी लगाने से एक घंटा दो घंटा बिजली देने से उसकी दुर्दशा होती है। उसको दो घंटे बिजली दी जाती है इससे उसका ट्यूबवेल चल गया खेत में पानी पहुंचा तब तक दो घंटे खत्म हो जायेंगे और बिजली चली जाती है और उस को पानी वहीं रोकना पड़ जाता है इससे किसान को कोई लाभ नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यवहारिक योजना बनाई जाए जिससे किसान को प्रोत्साहित किया जाए। जब किसान प्रोत्साहित होता है तो मैं समझता हूं कि उस इलाके का विकास होता है। वह मंडी और शहर आबाद नहीं होता जहां पर किसान की आर्थिक हालत अच्छी नहीं होती है। वह उजड़ जाता है, बरबाद हो जाता है। इसलिए किसान को बिजली की सुविधा दें, अस्पताल की सुविधायें। बहुत सी हमारी योजनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ले आई जाएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमारी योजनाओं का सामंजस्य जनता के साथ नहीं हो रहा है। जनता कहां क्या चाहती है उससे पूछा नहीं जाता है। जनता से ही नहीं कहीं कहीं तो केन्द्र और राज्य सरकारों में भी सामंजस्य नहीं होता है। कुछ योजनाएं केन्द्र से बनाई जाएं तो राज्य सरकार से नहीं पूछा जाता है। राज्य सरकार बनाएगी तो नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी यह भी देखने में आया है कि एक अफसर ऐसा आ जाता है वह अपनी मर्जी से योजना को चलाता है। दूसरा अफसर आता है तो वह भी अपनी मर्जी से योजना चलाता है। इसमें भी काफी हानि हमारे देश को हो रही है। एक बार हम किसी योजना को अन्तिम रूप दे दें लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख कर तो फिर उसको बदलने वाला कोई न हो न सरकारी अधिकारी, न मन्त्रिगण, न किसी इलाके

के लोग । इसलिए मेरा कहना यह है कि योजनाओं में भी सामंजस्य नहीं है । मैं इतना और कहना चाहूंगा कि हमारे सुकुल जी उस दिन बोल रहे हैं कि इलाहाबाद ने हमें चार प्राइम-मिनिस्टर दिये हैं मैं जानता हूं । जवाहरलाल जी के साथ हमारा बहुत सम्पर्क था । मैं आपको एक संस्मरण भी इस मौके पर सुनाना चाहता हूं । फजल अली कमीशन जब राज्यों के बटवारे के लिए बैठा तो हम यू.पी के बंटवारे के हामी थे । उन दिनों में जवाहरलाल जी के सामने हम आए। बहुत सी बातें करते करते हम ने कहा कि जितने सारे तर्क हम यू. पी. के बारे में देते हैं वह तो पब्लिक पसंद करती है एक बात हम पब्लिक को नहीं समझा पाते। वह बोले कौन सी बात है ? मैंने कहा कि जो हमारे यू. पी. के बंटवारे के खिलाफ लोग हैं वो यह कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भारत का यू.पी. की वजह से हैं, हम तो नहीं मानते । परन्तु यह बात सही है कि उस समय जवाहरलाल जी गुस्से में आ गये, अच्छा यह कहते हैं तो अब यू.पी. का बंटवारा जरूर होगा । कई बार उन्होंने आश्वासन दिया । दुर्भाग्य हुआ किदवई साहब की डैथ हो गई पंत जी को यहां आना पड़ गया । पंत जी दिल से नहीं चाहते थे उन्होंने पता नहीं जवाहरलाल जी को कैसे समझाया । कहने का मतलब यह है कि श्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, चाहे राजीव जी हों वह अकेले उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद की वजह से नहीं सारी देश की पब्लिक के लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया और वो अहल थे । अहल का मतलब यह है कि वे सारे देश को एक नजर से देखते थे । वही प्राइम मिनिस्टर अच्छा होता है । सुकुल जी ने थोड़ी चर्चा की फिर भी प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की हानि हुई हो ऐसा मैं नहीं जानता। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड एरियाज हैं। दिल्ली के आसपास चाहे राजस्थान को आप ले लीजिये जो अलवर का इलाका है वह दिल्ली के बार्डर से मिलता है, उसको भी बैकवर्ड एरिया घोषित किया गया है ।क्यों ? राजस्थान में अनेक बैकवर्ड एरियाज हैं, चूरू का जिला है, बीकानेर का जिला है । लेकिन दिल्ली के नजदीक कौन सा एरिया है? दिल्ली के नजदीक जमीन चाहिए, उद्योगपति को भी, अफसरों को भी और मजदूरों को भी । सब दिल्ली से दूर नहीं जाना चाहते हैं तो अलवर का इलाका जो लिया गया है बैकवर्ड एरिया में, वह हरियाणा का एरिया, यू.पी. का नाइडा का इलाका आप जानते हैं, इन इलाकों से दूर, दिल्ली से दूर इंडस्ट्री को फैलायें इंडस्ट्री के अलावा जो बिजली का काम है जिससे विकास होता है वह भी दूर के एरियाज को दी जाये । दूर के एरियाज को बिजली दी जायेगी तो जाहिर है मैं समझता हूं कि उसका विकास हो जायेगा । देश के किसी बैकवार्ड एरिया के अन्दर इंडस्ट्री खोल दो, वहां सड़क पहुंच जायेगी, बिजली पहुंच जायेगी, मोटर पहुंच जायेगी, स्कूल पहुंच जायेंगे, अस्पताल पहुंच जायेगा । उद्योगों का सही बंटवारा होना चाहिए । जहां तक खेती का सवाल है, खेती पर किसानों की तादाद घटानी चाहिए, वह बढ़ रही है । खेती पर जितने किसानों की तादाद घटती चली जायेगी उतना ही देश खुशहाल होता चला जायगा । दुनिया के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि जिन देशों में खेती पर कम से कम लोग हैं वे देश खुशहाल हैं । हमारे देश में खेती पर दबाव ज्यादा है और खेती की तादाद के मुताबिक उनको पूरी सुविधाएं भी नहीं हैं । फसल बीमे का सवाल है । कभी दुर्भाग्य से ओला वृष्टि हो, सूखा पड़े, अतिवृष्टि हो, बाढ़ हो तो क्या हो ? बाढ़ की समस्या स्थायी समस्या है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में सारी नदियों का झुकाव वहीं होता है । मेरे बाढ़ों के दृष्य देखे हुए हैं । फसल बरबाद होती है किसान बरबाद होते हैं । बाढ़ की रोकथाम हो सकती है इसके बारे में कोई स्थायी, योजना बनाई जा सकती है । इन योजनाओं को स्थायी बनाया जाये और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के विकास के लिए और मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि देश के जो भी अविकसित क्षेत्र हैं, उनको विकसित किया जायेगा तभी देश मजबूत होगा । मनुष्य का एक हिस्सा भी कमजोर है चाहे हाथ कमजोर है, पैर कमजोर है, दिमाग कमजोर है तो वह पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाता है । इसलिए वही राष्ट्र मजबूत कहलाता है जिसके सारे क्षेत्र विकसित हों और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वे भी एक तौर से विकसित हों । उनके भी विकास के बारे में हम सोचें । चाहे अविकसित क्षेत्र हों, चाहे अविकसित वर्ग हों चाहे आदिवासी

[श्री राम चन्द्र विकल]

हों, चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हों जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनकी तरफ भी विकास का प्रकाश पहुंचे तभी मैं समझता हूं देश का भला होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कल्पनाथ राय जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकारें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लए, गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चालू करेंगी । उद्योगों को सारे देश में बिखेर दें। दिल्ली के आस-पास उद्योग न हों । पहले वायुदूषण कराएंगे फिर रोकेंगे। बहुत सारी चीजें मेरी समझ से बाहर हैं । सरकार शराबबन्दी करती है और शराब बिक्री के लाइसेंस देती है । वायुदूषण को कराती है और दूर भी करती है । ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको सोचना चाहिए । पहले ही वायुदूषण ज्यादा न हो दिल्ली में, ज्यादा उद्योग न हों । पहले गंगा नदी में गंदगी डाल देंगे फिर सफाई की योजनाएं बनाएंगे । पहले बीमार न होने दें लोगों को क्योंकि बीमार होने पर इलाज पर खर्चा करते हैं । स्वास्थ्य के बारे में हमारी ऐसी योजनाएं होनी चाहिए कि बीमारी न हो । बीमार न होने दें । बीमार होने पर डाक्टर और दवाई पर कितना खर्च होता है, जान भी चली जाती है । मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं बताता कि स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे आदमी स्वस्थ्य रह सकता है बहुत छोटी छोटी बातों हैं । आज समय नहीं है फिर कभी किसी मौके पर मैं बता दूंगा । लेकिन हम बीमार होने पर इलाज के लिए सोचते हैं तो बीमार ही न हों इस पर सोचना चाहिए । हमारी योजनाएं सफल कैसे हों, वे घाटे की योजनाएं नहीं होनी चाहिए । मैं फिर आपका आभार करता हूं और कल्पनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका हृदय से समर्थन करता हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके नजदीक से मैं गया हूं जानता हूं और जो अविकसित हैं । मैंने समाज के लिए उस दिन चर्चा की थी, मैं कहना चाहूंगा कि समाज में हमारी कुछ परम्पराएं गलत पड़ गयी हैं इनको बदलना पड़ेगा । मैं पंजाबी भाईयों की बात करता हूं बिल्कुल उजड़ करके आये लेकिन हमसे आगे हैं । व्यापार में हमसे अधिक आगे हैं, फार्म में हमसे आगे हैं, ट्रंसपोर्ट में आगे हैं सबसे आगे क्यों हो गये हैं ? क्योंकि उनके यहां काम करने को अपमान नहीं मानते हैं । हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जातियां ऐसी हैं जो हल चलाने को अपमान समझती हैं, खेत जोतने को अपमान समझती हैं । तो ऐसी खराब मान्यता को हमें समाज से बदलना होगा। उसमें कल्पनाथ राय जी का हमको सहयोग चाहिए क्योंकि ऐसी भावना से जो किसी काम को करने में आज हम अपमान समझते हैं, तो फिर हमारा काम नहीं चलता ।

मैंने तो उस दिन शायद कहा था कि गेंदा सिंह ने हल चलाया था तो तमाशा हुआ, बड़े ढोल बजे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और वहां जलसा हुआ। गेंदा सिंह हमारे कृषि मंत्री हल चलायें, तो जातियां जो खेत में काम करने को अपमान समझती हैं, दूसरे कामों को करने में अपमान समझती हैं, हमें पंजाबी भाइयों से सबक लेना चाहिए । हर काम को करने में हम गौरव समझें । समाज में जो खराब मान्यताएं पड़ी हुई हैं, उनको भी तुड़वाने में हम मदद करें और सरकार से हम आर्थिक सहायता लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास करवायें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, मेरे दोस्त कल्पनाथ राय जी जो प्रस्ताव लाये हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए एक कमीशन की नियुक्ति के लिए, मैं उससे सहमत हूं ।

महोदय, यह सवाल सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश का नहीं या बिहार का नहीं मगर, देश में बहुत पिछड़े हुए हिस्से हैं, हर राज्य में कुछ ऐसे पाकेट्स हैं जिन एरियाज में अभी तक हमारे विकास की प्रक्रिया अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई और उसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां अभी तक बहुत पिछड़ापन रहता है ।

मैं महाराष्ट्र से आता हूं । हमारे यहां भी पिछड़ा हुआ एरिया है, मराठवाड़ा का विदर्भ का, कोन्कण का भी कुछ पिछड़ा

हुआ एरिया है । यह सब क्यों होता है, इन समस्याओं का हल क्या है ? यह समस्याए पैदा क्यों होती है, यह सब से बड़ा बात है उपसभापति जी, 12 लाख लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के बम्बई में रहते हैं और सारी बम्बई की पापुलेसन अगर देखी जाए तो 45 लाख लोग वहां स्लम एरिया में झोपड़-पट्टी में रहते हैं । उनके रहने के लिए घर नहीं है । यदि उस क्षेत्र में हम विकास करते, तो वहां से बड़े पैमाने पर बम्बई में नहीं आ सकते थे ।

तो सारे हिन्दुस्तान के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार का हो, पूर्वी बंगाल का, केरल का हो, आन्ध्र का हो, सारे हिन्दुस्तान से जो गरीब लोग हैं, जिन को मजदूरी नहीं मिलती उस स्थान पर लोकल कंडिशन में, उनका कोई आर्थिक हित अच्छी तरह से नहीं होता, तो वह लोग बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और ऐसे बड़े-बड़े शहरों की तरफ भागते रहते हैं । दिल्ली में भी समस्या पैदा होती है । तो हमारा बेसिक फाल्ट क्या है, हमारी गलती क्या है? मूलभूत हमारी उसमें क्या गलती हो चुकी है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि हमारे नियोजन मंत्री महोदय हमारे बारे में मिसअण्डरस्टैंडिंग न करें क्योंकि हम कुछ सुझाव रखना चाहते हैं ।

हमारे देश का जो राष्ट्रीय उत्पादन है वह 1947 से लेकर 1986 तक बहुत बढ़ा है । देश काफी तरक्की कर चुका है । यह हमारे लिए गौरव की बात है हमें बड़ा गर्व है कि हमारे देशवासियों ने बहुतसा योगदान करके इस देश को मजबूत बनाया, इकनामिक दृष्टि से मजबूत बनाया, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाया, आधुनिक उद्योग-धन्धों में मजबूत बनाया और भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर कर दुनिया में आया है, फिर भी हमारे देश में जो राष्ट्रीय उत्पादन है, वह दो लाख दस हजार करोड़ होता है हर साल । उसमें से 46 प्रतिशत कृषि से आता है और शायद मेरे कुछ परसेंटेज 1-2 इधर-उधर हो सकते हैं, मगर हमारी कृषि जो है, यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट उद्योग है मगर हमारी बदकिस्मती यह है कि आज तक हमने कृषि को उद्योग नहीं समझा, न लोग समझते हैं, न आफिसर्ज समझते हैं, न राजनीतिज्ञ समझते हैं और मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हिन्दुस्तान और चीन यह दो देश दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनकी इकानमी आर्थिक परिस्थिति कृषि बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी है और बाकी सारे यूरोपियन कण्ट्रीज, अमरीका हो या और हैं, एशिया है या सारी दुनिया के जो देश हैं, उनकी इकानामी इंडस्ट्रियल बेस्ड है क्योंकि कृषि के लिए हमारे पास जो सुविधाएं हैं, नैसर्गिक सुविधायें हैं, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट भी रहा हूं साइंटिस्ट भी रहा हूं और किसान भी रहा हूं । जिस देश में सूर्य प्रकाश ज्यादा होता है, वहां का क्लाइमेट खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, जिस देश में सूर्य प्रकाश अच्छा होता है, वहां रेनफाल अच्छा होता है, जिस देश में सूर्य प्रकाश अच्छा होता है, वहां सारे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे होते हैं । और हमारी किस्मत से भारत में सनलाइट बहुत अच्छी तरह से है । काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ड्यूरेशन आफ सनलाइट जिसको कहते है वह बहुत बड़ा है । उस लिहाज से हमारे यहां जो बारिश होती है जो नैसर्गिक हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं वे दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं हैं । हमारे पास क्या कमी है, हमें क्या सोचना चाहिए, हमें कृषि को कैसा महत्व देना चाहिए वह हमने अभी अच्छी तरह से सोचा भी नहीं है । राष्ट्रीय उत्पादन का दो प्रतिशत जो हम कृषि पर खर्च करते हैं, जहां से 46 परसेंट नेशनल वैल्थ तैयार होती है और इसीलिए कृषि पिछड़ी हुई रही है । अगर योजना मंत्री मुझ से मंजूर नहीं करेंगे मैं कहता हूं कि कृषि उसके बाद एन-आर ई पी, उसके बाद जो-जो योजनाएं हैं कृषि की जो बिजली लगती है एनर्जी और कृषि के सारे उद्योग और अगर हम प्लानिंग में देखे कि जितना पैसा मारों को लगा है यह सारा कृषि पर खर्च होने वाला पैसा देश के नियोजन में जितना पैसा खर्च होने वाला है उसके 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है । हमारे पास मूलभूत समस्या यह है कि जहां 70-75 प्रतिशत लोग रहते हैं वहां 20 प्रतिशत पैसा खर्च होता है । यहां 20-25 प्रतिशत लोग रहते हैं वहां 75 प्रतिशत पैसा खर्च होता है । इसलिए जहां पर पैसा दौलता है उधर ही लोग भागते रहते हैं । शहरों की ओर लोग ज्यादा भागते हैं । यह बम्बई शहर देश की 32 परसेंट

[श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव]
इकोनोमी कन्ट्रोल करता है । मैं यह नही कहता कि मैं बम्बई का हूं और इसको अधिक सुविधाएं दी जाएं । इस विचार का मैं नहीं हूं । क्योंकि बम्बई ही महाराष्ट्र नहीं है । महाराष्ट्र वह है जो पिछड़ा हुआ गांव है हमारा मराठवाड़ा और विदर्भ है जहां अभी तक प्रगति का विशेष प्रयास नही हुआ है, वह सही महाराष्ट्र है । गांधी जी ने कहा था कि असली भारत देहात में रहता है, ग्रामों में रहता है और वह ग्रामोद्योग जो है इसका मतलब यह है कि गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि सूत कातना और उसके बाद हाथ से काम ज्यादा करना जिससे कि रोजगार ज्यादा हो । बल्कि ग्रामोद्योग का मतलब यह है कि जो हमारे पास मजदूर हैं वे ज्यादा कुशल नहीं हैं, ज्यादा ट्रेड नही हैं, वह भी जो छोटे-छोटे उद्योग बना सकते हैं वह असल रूप में ग्रामोद्योग है । आज ग्रामोद्योग वह भी हो सकता है जो इलैक्ट्रिक मोटर देहात में लगती है हमारे बावड़ी में से पानी निकालने के लिए और हमारा जो उत्पादन दिल्ली में होता है, बम्बई में होता है वह भी ग्रामोद्योग में आ सकता है । यह जरूरी नहीं है कि बम्बई में और दिल्ली में उसके कारखाने लगें, वह ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जहां उसकी ज्यादा दिक्कत है उस क्षेत्र में जहां कारखाने लग सकते हैं और लगने चाहिए । उत्तर प्रदेश को इतना गौरव है कि हमारे देश के प्रदूषण मिटाने की बात कर रहे हैं । राम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और कृष्ण उत्तर प्रदेश में पैदा हुए ।

श्री वी. सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश): कृष्ण तो द्वारिका में रहे ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : वह पैदा तो मथुरा में हुए । आप द्वारिका के गांधी जी रहे हैं गुजरात को वह छोड़ दीजिए। मगर जहां गंगा नदी बहती है वह भी राम तेरी गंगा मैली हो गई, ऐसी बात हो चुकी है । वह भी गंदी कर दी है हमारे देश के लोगों ने अपने पाप धो-धो के और हम नदियों के प्रदूषण मिटाने की बात कर रहे हैं । हम लोग पहले उसे गंदा करते हैं और फिर उसके बाद उसको साफ करने को कहते हैं । जो पवित्रता होती है वह दिल की पवित्रता होती है । नदियों में नहाने से कभी जिस्म पवित्र नहीं होता । तुम किस तरीके से सोचते हो, तुम किस तरह से रहते हो, तुम किस तरह से बर्ताव करते हो, उस पर पवित्रता डिपैंड करती है । मान्यवर इसके बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए । यह पिछड़ापन कैसे जा सकता है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो । पहली बात है हमारे खेत के लिए पानी, पहली बात है हमारे खेत के लिए बिजली और वहां ग्रामोद्योग जैसी बहुत महत्वपूर्ण समस्यायें हैं । पानी तो बहुत है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है । हमें बड़ा आश्चर्य हुआ एक बार जब आपातकाल आया था तो बिहार में लोगग भूख-प्यास से तड़फ रहे थे । 10 फीट नीचे गए तो पानी ही मिलता है मगर पानी को निकालने के लिए यन्त्र चाहिए । यह छोटी टैक्नालोजी है । यह हमारे पास बड़े पैमाने पर उपलब्ध नही है । जो अंडर-ग्राउंड पानी है वह कितना है ? वह हमारे गांव को पता नहीं । उसके बारे में सर्वे चाहिए । उसके बाद पानी निकालकर जब तक हम किसान को खेती के लिये नहीं देंगे तब तक किसान उसे प्राप्त नहीं कर सकता । क्योंकि उसकी आर्थिक क्षमता खत्म हो चुकी है । वह कुछ खरीद नहीं सकता । वह क्यों नहीं खरीद सकता ? अगर 1970-71 का हम प्राइस इंडैक्स देखें, आज 340 है, 360 है, मगर कृषि की कितनी है, 160 प्रतिशत से ऊपर नहीं पड़ता । उस वक्त 70 रुपए क्विंटल ज्वार हमारे महाराष्ट्र में थी, आज 130 रुपए है, तो यह तो 200 प्रतिशत भी नहीं है, जबकि बाकी की 300, 400, 500 प्रतिशत तक बढ़ी है । तो जब तक किसानों को सही मूल्य नहीं देंगे, उनकी खेती के बारे में रेमुनरेटिव-प्राइसेज नहीं देंगे, तब तक हमारा किसान आगे नही बढ़ सकता । हम किसानों को किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए, किसी प्रकार की सबसिडी नहीं चाहिए, कोई माफी नहीं चाहिए, हम जो पैदा करते हैं, हम जो अनाज पैदा करते हैं, जो हम खेतों में हल चलाते हैं, हमारे घर की बहू-बेटियां और बाप-दादा जो मेहनत करते हैं, वहां जो पसीना बहाते हैं, उसका मुआवजा चाहिए । हमको उसकी कीमत नही चाहिए, उसका मुआवजा चाहिए । हम समझते हैं कि देश के लिए हम काम करते हैं और देश के लिए काम

करना हमारा फर्ज है। जैसा कि पंडित जी ने कहा था एक दफा कि सारे लोग हक मांगते हैं, लेकिन जो इंसान का फर्ज होता है, अगर वह इंसान अपने फर्ज को पूरा नहीं कर सकता, वह हक नहीं मांग सकता। आज हिन्दुस्तान का किसान जो है; उससे कोई कहे या न कहे, वह अपना फर्ज पूरा करता है, चाहे बारिस हो, वह अपने खेत में बोता है और अगर बोएगा नहीं तो खाएगा कहां से। वह अपना फर्ज समझता है और अपना काम करता है।

आज आप आयल-सीड 1500 करोड़ का बाहर से मंगा रहे हैं। मैं आपको, सरकार को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे अलसी के फूल का, सूरज फूल का या सोयाबीन या कोई और क्राप, जो आयल तैयार करने वाले हैं, उनका रेम्युनरेटिव प्राइस आप दें तो आप को यह 1500 करोड़ का इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए हमें एक आर्थिक नीति बनानी पड़ेगी, जिससे सारे एरिए का पिछड़ापन पीछे जा सकता है। अब इस साल के सारे बजट में एक हजार करोड़, अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन चार प्रतिशत से ज्यादा पैसा कृषि पर खर्च नहीं किया जा रहा है, इस नेशनल बजट में से। सारा हम देखें, कृषि पर खर्चा, ग्रामीण विकास पर खर्चा, उसके बाद एन.आर.ई.पी., आई.आर.डी.पी. और जो योजनाएं ऐसी हैं, वह सारी देखें तो 10 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा नहीं है। तो यह मूलभूत समस्या हमारे सामने है।

उपसभापति महोदय, आज बड़े शहरों में तो पढ़े-लिखे लोग, जो कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, वह तो संगठित हैं और संगठित होकर अपनी आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज के आगे सरकार, चाहे उस पार्टी की हो या हमारी पार्टी की हो, उसको दबना पड़ता है और ये लोग अपनी समस्या मनवा लेते हैं। लेकिन हमारे करोड़ों लोग, जो देहात में रहते हैं 40-45 करोड़ लोग, वह संगठित नहीं हैं, उनकी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वह अपनी आवाज उठाएं। अगर उठाएंगे, तो क्या खाएंगे। यह हमारे सामने बड़ी समस्या है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ लोग ज्यादा ले लेंगे और हमारे लोग भूखे रहेंगे, जिसके पास ज्यादा है, वह ज्यादा लेंगे। अब बम्बई में महाराष्ट्र की पर कैपिटा इन्कम 3000 रुपए है, यहीं टाटा और बिरला बसे हैं, उनकी दो-दो, तीन-तीन हजार करोड़ की इण्डस्ट्री लगी हुई है, दूसरी ओर महाराष्ट्र में लंगोटी पहन कर रहने वाले कोंकण के मेरे भाई हैं, जो चाय का काम करते हैं और उनकी आमदनी सौ रुपए है। यह इस तरह समाजवाद नहीं आ सकता। अगर समाजवाद लाना है, तो हमें कड़े कदम उठाने होंगे, उसके लिए सांस्कृतिक-क्रांति करनी चाहिए, चाहे कोई कितना चिल्लाए, हमें अपने देश में लोगों को सामाजिक न्याय देना चाहिए, *आर्थिक न्याय देना चाहिए। जब तक हम यह नहीं देंगे, तब तक गांधी जी का सपना,* पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का सपना और इंदिरा जी का सपना पूरा नहीं कर सकते। इसलिए उस रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है।

उपसभापति महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं पानी के बारे में, बहुत पुरानी योजना जब हमारे दोस्त के.एल. राव, इरीगेशन मिनिस्टर थे, गंगा-कावेरी एक योजना थी, उस वक्त योजना का लिंकिंग आफ रिवर, उसकी 20 हजार करोड़ एस्टीमेट थी, आज उसकी वही योजना हमें पूरी करना हो तो शायद एक लाख करोड़ से ज्यादा खर्च होगा।

SHRI DARBARA SINGH (Punjab): But that was impracticable.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : मेरा सजेशन है।

It might be impracticable; and therefore they might not have accepted.

3 P.M.

अगर इन नदियों को जोड़ें और जो पानी बह जाता है उसका उपयोग करें तो फैमिन और ड्राट एरियाज को पानी मिल सकता है। कुछ लोग इसको इम्प्रैक्टिकल कहते हैं इसलिए कि ज्यादा पानी दक्षिण भारत में चला जायगा। मैं यह नहीं कहता कि उत्तर भारत में पानी पूरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन पानी का पूरा उपयोग करने के लिए नदियों को जोडा जाना चाहिए, चाहे उसमें दस-बीस साल लगें। इसके बारे में गम्भीरता से सोचना बहुत जरूरी है।

[श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव]

उपसभापति महोदय, बापू कलदाते रिजोल्यूशन लाए थे बैकवर्डनेस निकालने के लिए स्टेटूटरी कमीशन बनाने की। सारे लोगों ने उसका समर्थन किया, हमारी पार्टी के लोगों ने किया अपोजिशन पार्टी के लोगों ने किया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सरकार को मुश्किल में डालना चाहते हैं। बात यही है कि हमारे दिल में दर्द है और हम चाहते हैं कि हमारा पिछड़ापन जाना चाहिए। उस लिहाज से हमारे नए मुख्य मंत्री लिए वे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं-मराठावाड़ा और विदर्भ पर। महाराष्ट्र की असेम्बली ने यूनेनीमस रिजोल्यूशन दिया था कि स्टेट्यूटरी बोर्ड की निर्मिति करो या कोई इम्पार्शियल जज नियुक्त किया जाय। पहले देखना चाहिए कि बैकवर्डनेस क्या है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हिन्दुस्तान के जो बैकवर्ड हिस्से हैं उनकी बैकवर्डनेस दूर की जानी चाहिए एक, दो, तीन योजनाओं में बैकवर्डनेस जानी चाहिए।

मैं यह नहीं कह सकता कि पूरी योजना बदलनी चाहिए, मगर राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का जो हिस्सा है उसी हिसाब से देश के नियोजन में कृषि पर खर्च होना चाहिए। इस लिहाज से खेती में लगने वाली चीजों पर बराबर खर्च होना चाहिए।

मैं बहुत खुश हूं कि मेरे दोस्त कल्पनाथ राय जी ने यह सवाल उठाया है। यह राष्ट्रीय सवाल है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ तो भारत आगे नहीं जा सकता। कहीं चोट लगती है तो दिन भर शरीर को तकलीफ होती रहती है। इसी तरह पिछड़ेपन का दर्द हमारे शरीर पर है, उसको हमें दूर करना है। उस के लिए जिनके पास बहुत कुछ है उसको ले लिया गया है। बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाने में कुछ देरी नहीं लगेगा। जब हमारे देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समस्या आई थी तो इस देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों और प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बैंक खत्म हो गए, बैंकों का पैसा खत्म हो जायगा, मगर उनकी बदकिस्मती और गरीबों की खुश-किस्मती से आज बैंकों की शाखाएं 50 हजार हो गई हैं और उनमें लगा रुपया 75 हजार करोड़ हो गया है, जबकि पहले 8 हजार करोड़ रुपया था और शाखाएं 5 हजार थीं। बड़े उद्योगपति अपनी इंडस्ट्री को सिक बना कर पैसा खाते हैं। प्रधान मंत्री जी का बयान आया है कि जो कारखाने अच्छी तरह से नहीं चलेंगे, घाटे में चलेंगे उनको बन्द करेंगे। जो बड़े-बड़े उद्योग हैं जरूरत की चीजें बनाते हैं और प्राइवेट लोगों के पास हैं, दाम ज्यादा खाते हैं और उत्पादन कम करते हैं ऐसे उद्योगों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है।

ऐसा किया जाय तभी हमारे देश में समाजवाद आ सकता है। इस पिछड़ेपन को हटाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये जिसमें हमारे देश में पिछड़ेपन का सही नक्शा सामने आए और उस पिछड़ेपन को हटाने के लिए हम मिलकर--चाहे हम किसी भी पार्टी के हों--कदम बढ़ाना पड़ेगा और हमारे रास्ते जो भी रुकावटें आए उनको हटाने की हिम्मत रखनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दे सकते। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री कैलाश पति मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं कल्प नाथ राय जी के इस प्रस्ताव का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ेपन की जांच के लिये और उस के निदान के लिये एक आयोग गठित किया जाये। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जो इस क्षेत्र के बाहर के मित्र हैं वे रातदिन वहां रहने वालों की पीड़ा थ्योरिटिकली तो समझ सकते हैं लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव उसी को होता है कि जो उस क्षेत्र से आ रहा है। उस में भी थोड़ा बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्तर तो ऊपर है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार का स्तर एक जगह पर खड़ा दिखाई देता है। सरकार के पास सब प्रकार के आंकड़े हैं। प्लानिंग कमीशन के पास सब प्रकार के आंकड़े हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उन आंकड़ों का कब अध्यन होता है? उन आकड़ों के अध्ययन से कोई निष्कर्ष निकलता है या नहीं और उस से कोई नतीजा निकालने की मंशा दिखाई देती हो, इस का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तीन, चार मोटी मोटी बातें हैं। यदि सरकार उन आकड़ों को देख लेती तो उस की समझ में आता कि शरीर के किस

अंग में कष्ट है, कहां कटा फटा है और फिर उसका मुनासिब इलाज हो सकता था ? पर कैपिटा इन्कम और पर क्पैपिटा पावर उवैलिबिलिटी कितनी और कहां पर क्या है और उस के आधार पर पर-कैपिटा इरिगेशन का जो आंवटन सातवीं योजना में दिखाई देता है उस का आपस में कहीं तालमेल मुझे दिखाई नहीं देता । मुझे भारत का पूरा नकशा दिखाई देता है और मैं यहां हर राज्य की पर कैपिटा इन्कम का उल्लेख करना चाहता हूं । पूरे 22 राज्यों का उल्लेख करना तो संभव नहीं है लेकिन आज ऐसे भी राज्य हैं जिन की पर कैपिटा इनकम 3560 है, ऐसे भी राज्य हैं जिन की पर कैपिटा इनकम 3059 है और ऐसे भी राज्य हैं जिन की रिकैपिटा 1955 है और जिस राज्य से मैं आ रहा हूं आप उस का विवरण भी सुन लीजिए । बिहार की पर कैपिटा इन्कम 1174 है । पूरे 22 राज्यों में सब से नीचे स्तर पर और इससे जो थोड़ा ऊपर है सिक्कम उसकी है 1300। अब सिक्कम में खेती की जमीन कितनी है और खनिज पादार्थ कितने है, और सारी स्थितियां डेवलपमेंट के लिये कितनी है, लेकिन वह भी बिहार स कम से कम 200 पर कैपिटा आकड़ों में ऊपर है । बिहार की मात्र 1174 है जब कि 22 राज्यों की तुलना में देश की आबादी का दसवां हिस्सा उस की आबादी है और वह सब से निचले स्तर पर 1174 की पर कैपिटा इनकम ले कर खड़ा है जबकि कि देश के एक भाग में इन्कम 3560 है। तो क्या बिहार के किसी नागरिक को या प्रतिनिधि को भाषण दे कर ही सरकार संतुष्ट करना चाहती है ? एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूं । अगर कोई बड़ा भारी रेगिस्तानी क्षेत्र होता, बड़ी कठिनाई होती उसके आर्थिक विकास में तो मैं समझ सकता था। लेकिन वह कैसा राज्य है जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है। खनिज पदार्थों की बहुतायत है । पूरे देश में जितना खनिज पदार्थ होता है उसकी 42 प्रतिशत केवल बिहार के अन्दर पैदा होता है । सिंचाई की क्षमता है । इतना अच्छा जंगल है कि एशिया में, दुनिया में सबसे पहले स्थान पर बिहार का नंबर है । सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा जंगल है । पहाड़ी क्षेत्र है, पत्थर है, सड़कों पर लगने वाली गिटियां बिहार में होती है । हिन्दुस्तान में किसी भी स्थान पर ऐसा पत्थर नहीं पाया जाता जैसा बिहार में है । आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा खनिज भंडार है, नदियों का जाल है, श्रेष्ठ कोटि के जंगल है और बिहार आज सबसे नीचे के स्तर पर आकर खड़ा हुआ है ।

श्रीमन, अभी तीन दिन पहले रेल बजट पर मैं बोल रहा था जब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया । मैंने कहा था कि बिहार में रेल की पटरी छटे स्थान पर है । एक भी क्षेत्रीय कार्यालय वहां पर रेल का नहीं है । खनिज पदार्थों से छोटा नागपुर भरा हुआ है, बायोलाजिकल सर्वे से यह सिद्ध हो चुका है, लोहा, अल्मूनियम, कापर, आदि उठाने के लिए मैं समझता हूं कि 50 हजार से ऊपर रोज ट्रक बिहार क्षेत्र में जाते हैं । ट्रकों पर मोबिल लगता है, डीजल लगता है, पैट्रोल लगता है । लेकिन आयल कंपनियों का जाल वहां दिखाई देने पर भी एक भी हेड आफिस किसी आयल कंपनी का वहां नहीं है । परिणाम यह हो रहा है कि जो 6 टैक्स का असैसमैंट है, उससे भी बिहार मारा जा रहा है । किसी आयल कपनी का हेड आफिस कलकत्ता में है, किसी का बम्बई में है और कहने के लिए कुछ थोड़े से नाम गिनाए जा सकते हैं जैसे टाटा की एक फैक्टरी लगी उसका भी हेड आफिस है, लेकिन आश्चर्य लगता है यह देख कर कि इतने सारे बैंकों की शाखाएं वहां पर है, लेकिन किसी का आफिस वहां पर नहीं है ।

श्रीमन, अगर आप सारे भारत के प्रान्तों का क्रेडिट रेशियो मंगाकर देखें तो किसी राज्य में 120 प्रतिशत क्रेडिट रेशियो है, किसी में 111 प्रतिशत है, बहुत कम ऐसे राज्य हैं जिनका क्रेडिट रेशियो 82 परसेंट से नीचे होगा । लेकिन बिहार में क्रेडिट रेशियो बैंकों का केवल 17 प्रतिशत है । यह 1978 की बात मैं आपको बता रहा हूं । उस आंकड़े को तोड़कर देखें तो यह क्रेडिट रेशियो किसानों में कहां तक पहुंचा है, गांव के अन्दर जो लोहार है, चमार है, बढ़ई है, कारीगर है, उनके बीच में केवल 6 प्रतिशत पहुंचा है । थोड़ी बहुत कोशिश करके यह बढ़ा था, लेकिन इस बार फिर गिर गया है । राष्ट्रीयकृत बैंकों में बिहार का गरीब आदमी पैसा जमा करता है, लेकिन खर्च करने के लिए, उपयोगी करने के लिए बिहार के लोगों को

[श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव]

वह राशि नहीं मिल रही है । आयल कंपनियों का आयल बिकता है, लेकिन एक भी हैड आफिस बिहार में नहीं है । केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है? मैं आयोग का समर्थन इसलिए कर रहा हूं एक बार जब यह पूछा गया था कि बिहार के अन्दर जो जंगल हैं, फारेस्टस हैं उसके आधार पर कितने उद्योग, कुटीर उद्योग चल सकते हैं? मुझे याद है उस समय यह कहा गया था कि 104 ऐसी इन्डस्ट्रीज चल सकती हैं । खनिज के ऊपर आपने कितने उद्योग लगाये ? बरौनी में एक खाद का कारखाना लगा कर बैठ गये तब से लेकर मांग हो रही है आक्जलरी इंडस्ट्री को खड़ा किया जाए और पैट्रो इंडस्ट्री उसकी सहायता के लिए लगाई जाए लेकिन कुछ नहीं हुआ । कुछ न कुछ उलट-पुलट कर उत्तर दे दिया जाता है । बिजली कैसे बढ़े इस ओर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया । उद्योग कैसे बढ़े इस ओर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया । जो उद्योग इस वक्त लगे हुए हैं वे भी एक-एक करके मर रहे हैं । इसी सदन में डालमिया नगर के बारे में चर्चा उठी थी । दो साल से अधिक हो गये । 20 हजार कर्मचारी वहां पर काम करते थे और दो साल से घाटा न देने वाला उद्योग, मुनाफा देने वाला उद्योग कारखाना बंद पड़ा हुआ है । उसमें ताला लगा हुआ है । उद्योगपति और सरकार की, समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार की नजरी है । अगर वह उद्योगपति उसको नहीं चला सकता या नहीं चलाना चाहता तो उसको सरकार टेक-ओवर कर ले और टेक-ओवर करने के बाद अगर खुद नहीं चला सकती है तो दर्जनों तैयार हैं जो इसे चला सकते हैं आप उनको दे दीजिए । लेकिन एक ही सज्जन की मुठठी बन्द करके आप चलाना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है । 20 हजार कर्मचारी जो उसमें काम करते थे, बेकार हैं उनके बारे में अखबार में भी छपा था और मैंने भी आपको बताया था कि जब से कारखाना बन्द कर दिया गया, ताला लगा दिया गया है तब से 100 के लगभग कर्मचारी भूखों मर रहे हैं । किस का धन व्यय हो रहा है? भाषण हम लोग देते हैं और चले जाते हैं लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कहने को तो हम एम. पी. साहब हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं । हम सिर्फ बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं । कौन इसका समाधान करेगा ? कौन उनकी दरिद्रता को दूर करेगा ? सातवीं, आठवीं और सैकड़ों पंचवर्षीय योजनाएं चलती जायेंगी मैं कहूंगा कि अगर रोग का निदान नहीं किया गया, परिस्थिति को देखा नहीं गया तो उनका कोई भला होने वाला नहीं है । वे तो ऊपर नहीं उठने वाले हैं बल्कि देश भी ऊपर नहीं उठने वाला है । इसी साल के बजट में बिहार में एक किलोमीटर रेल की पटरी बढ़ाने का प्रावधान नहीं रखा गया, एक छोटा सा उद्योग लगाने का प्रावधान नहीं रखा गया, मरते हुए उद्योगों को जीवित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, किसानों के खेतों को पानी पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया कृषि के ऊपर आधारित कौन-कौन उद्योग खड़े हो सकते हैं, इसका प्रावधान नहीं रखा गया । जंगल में क्या उद्योग लग सकते हैं, खनिज के ऊपर क्या उद्योग लग सकते हैं, पत्थर के ऊपर क्या उद्योग लग सकते हैं इस के लिए एक भी प्रोजेक्ट का आपने जिक्र नहीं किया । मैं कहना चाहता हूं कि रेल के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की आप गिनती कर रहे हैं, बड़े-बड़े प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं लेकिन क्या इसमें से कोई प्रोजेक्ट बिहार में नहीं लगा सकते थे ? बिहार की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? कितने दिनों तक उपेक्षा करते चले जायेंगे ? साढ़े सात करोड़ की आबादी के इलाके की अगर लगातार किसी प्रकार से उपेक्षा करते चले जायेंगे तो आप वहां से क्या उम्मीद कर सकते हैं । मैं जानता हूं आज प्राइवेट बिल है और मैं समझता हूं यह ऐसे ही रह जायेगा । लेकिन जो दर्द है, जो वेदना है, जो बेचैनी है उसको जरा अनुभव करें और आप आयोग गठित करने से रुके नहीं । जैसे छोटी-छोटी बात के लिए आयोग गठित करने पड़ते हैं इसी तरह से इसको एक महत्वपूर्ण चीज समझ कर इसके लिए एक आयोग गठित कर दें । इन शब्दों के साथ मैं श्री कल्पनाथ राय को हृदय से बधाई देता हूं और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

SHRI DARBARA SINGH: Sir, I would like to bring to your notice just this much—that the Resolution which has been brought forth by the honourable ember is confined to Uttar Prades only. I appreciate his

Resolution.

SHRI KAILASH PATI MISHRA: There is an amendment.

SHRI DARBARA SINGH: I am not concerned with your amendment.

Sir, the Resolution which has been brought forth is to bring to the notice of the Government that that part of Uttar Pradesh which is much more important is neglected. The economic conditions there worry the honourable Member, the party and other parties as well. But such a situation is there not in U.P. only. If you look at the whole of India, there are parts which are most backward. There also industry is not developed; I mean small-scale industry. I do not want that big industry should be there. But small-scale industry means more employment. Therefore, industry should be there, water distribution should be properly done and roads should be built so that people can progress more. Development of both agriculture and industry should be there. It is good that he has brought it to the notice of this House though it relates to the U.P. area only. But we are very much concerned that it should be taken up for India as a whole. This also I would like to bring to your notice, Sir.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे श्री कल्पनाथ राय जी ने जो रिजोल्यूशन सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी-अभी हमारे आदरणीय बाबू दरबारा सिंह जी ने कुछ बातों की ओर इशारा किया। मैं उनसे इस बात में पूर्णत: सहमत हूं और उसमें एक बात यह भी जोड़ देना चाहता हूं कि जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां पंजाब और हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे हिस्सों में विद्यमान हैं जिनकी वजह से वहां एन्सीलरी इंडस्ट्रीज या छोटे-छोटे उद्योग धन्धे वहां पर लगे, शायद वे परिस्थितियां हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हैं और परटिकुलरली यह) चीज भी जोड़ देना चाहता हूं, हालांकि रिजोल्यूशन में यह नहीं है, बिहार में भी नहीं हैं। इन सब बातों को लेकर एक ऐसा वातावरण बनकर तैयार हुआ कि पूरा भारत जब दिन प्रति दिन तरक्की करता चला जा रहा है तो उसमें हमारी तरक्की की गति बहुत धीमी है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि हमारे यहां कोई काम नहीं हुआ है। हमको सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ट्यूबवैल्स और नहरें दी गई हैं, सड़कों का भी निर्माण हुआ है। रेलवे लाइन्स हमको दी गई हैं। कुछ छोटे-मोटे कारखाने भी हमको दिये गये हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए और इतने बड़े क्षेत्र के लिए यह बिलकुल नाकाफी है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। इस संबंध में दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारे पिछड़ेपन कारण आर्थिक है और दूसरा सामाजिक है। राजनैतिक पिछड़ेपन को मैं नहीं मानता। यह जो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है, इसके पीछे आज की परिस्थिति नहीं है, बल्कि आज से पूर्व सैकड़ों सालों की परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आजाद होने के बाद पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे स्थान रहे हैं जहां पर नहरों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसके पहले कहीं पर कोई नहर नहीं थी। आप को श्रीमन, मैं एक चीज बतला दूं। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और उसके बाद फिर छपरा और चम्पारण और बिहार के जिलों के अन्दर सब मिलाजुलाकर आप देखें तो इंडस्ट्री के नाम पर केवल गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना है, बाकी कुछ नहीं है। वहां छोटी-छोटी गन्ने की मिलें हैं जिन में काश्तकारों के गन्ने की पिराई होती है। उससे कोई काम चलता नहीं है। इनमें बहुत सारी प्राइवेट हैं। लेकिन असलियत यह है कि जहां मुल्क के अन्दर आप इतने सारे कल कारखाने लगा रहे हैं तो क्या यह क्षेत्र इसके योग्य नहीं है? मैं मानता हूं कि रा-मैटीरियल इसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उस रा-मैटीरियल के लिये हम जमीन देने के लिये तैयार हैं, हम सस्ती लेबर देने के लिये तैयार हैं। आप बहुत सारी इंडस्ट्री पंजाब और हरियाणा को दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या खनिज सम्पदा वहां पर है? मिनरल रिसोर्सेज वहां पर उतने कतई नहीं हैं जितने कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। मिनरल रिसोर्सेज भी हम देने के लिये तैयार

[श्री सुखदेव प्रसाद]

है। हां, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि वहां पर पावर की कमी जरूर है लेकिन इसके लिये हम नेपाल से समझौता करके पावर की व्यवस्था कर सकते हैं जहां पर नदियों के स्रोत बहुत काफी हैं। तो श्रीमन, इन सब बातों को देखकर इंडस्ट्री का विस्तार किया जा सकता है। किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिये केवल एक खेती ही जिम्मेदार नहीं होती। उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी का सारा बोझ खेती पर है और आज आप देखेंगे कि हमारा लेबर उससे भी बच रहा है। आप दिल्ली के स्टेशनों पर जाकर देखिये, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर झोला लटकाये हुए, लुंगी पहने हुए, कमीज पहने हुए हजारों की तादाद में दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र इतना दुर्भाग्यशाली है, जो रेल बिहार से दिल्ली आती है उसमें एक रेल जयन्ती जनता एक्सप्रेस है, इसमें आने वाले ये मुसाफिर हजारों की तादाद में बैठते हैं और वे नीचे से लेकर ऊपर तक बैठते हैं और कहीं पर किसी पुल से टकरा जाते हैं और काफी तादाद में मारे जाते हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कई बार इस तरह की दुर्घटनायें हो चुकी हैं लेकिन इसी तरह से फिर भी वे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जाते हैं और ऐसी जगहों पर काम करके जो पैसा मिलता है उससे अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि यह पिछड़ापन क्यों है और इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज एक हमारी सामाजिकता है और उस सामाजिकता के पीछे और कोई बात नहीं केवल हमारा एजूकेशनल बैकवर्डनेस है। हमें ऊंचे स्कूल नहीं मिल पाते, हमारे बच्चों को नहीं मिल पाते, हमारे लड़के-लड़कियों को नहीं मिल पाते जिसकी वजह से आज भी समाज में वे पुरानी कुरीतियां, जो पहले से विद्यमान थीं, वे आज भी विद्यमान हैं और हमारे पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है और इसकी वजह से हर आदमी हर रोजगार को वहां पर नहीं कर पा रहा है। इसलिये जरूरी है, एक गोरखपुर में यूनिवर्सिटी है, बाकी चारों तरफ जो यह क्षेत्र शिक्षा के मामले में खाली पड़ा हुआ है वहां पर यूनिवर्सिटी खोली जाये या बहुत सारे उद्योग धंधे खोले जाये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप जगह-जगह पर डिग्री कालेजों की व्यवस्था कर दीजिये ताकि इस क्षेत्र के लोग एजूकेशन काफी तादाद में पा सकें अगर एजूकेशन बढ़ेगी तो लोगों में एक नई चेतना आयेगी और उससे उनमें काम करने की भावना बढ़ेगी। तीसरी बात है कि जो हमारी छोटी-मोटी इंडस्ट्री है जैसा कि हथकरघा है, या शुगर है तो इसके द्वारा उत्पादित मालों की खपत की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिये हमारे पास मार्केट होना चाहिए ताकि बिचौलिये बीच में न आ सकें। मार्केट में बिचौलियें इन सामानों को खरीदकर ले जाते हैं और दूसरे मार्केट में बेच देते हैं और सारा मुनाफा वे ले जाते हैं और हमारे कारीगर थोड़ा बहुत मुनाफा पाकर ही रह जाते हैं। श्रीमन्, हमें एक चीज बतला दें, हमारे यहां लकड़ी की बहुतायत है, बांस की बहुतायत है, गन्ने की बहुतायत है, धान की परियाल की बहुत ज्यादा बहुतायत है। क्या इससे कागज के कारखाने नहीं लगाए जा सकते हैं? इससे बड़े मजे से कारखाने चल सकते हैं। लेकिन उनकी बात को जाने दीजिए हमारी तरफ तो चावल मिलें तक भी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को यह सब चीजें छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। उनमें लोगों को लगा कर के काम की व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एंसीलरी इंडस्ट्रीज भी उसी जगह पर होती हैं जहां उसके आस पास के इलाके में कोई बहुत बड़ा कारखाना हो बहुत बड़ा उद्योग हो। हमारे यहां तो कोई बहुत बड़ा कारखाना ही नहीं है तो ऐसी सूरत में उसको प्रोत्साहित करने के लिए जगह-जगह जहां पर बहुत कारखाने खोले जा रहे हैं उस एरिया में भी कुछ हेवी इंडस्ट्री के कारखाने स्थापित करने चाहियें ताकि ठीक से काम चल सके और उसके साथ साथ जो वहां पर एकाध छोटा-मोटा कारखाना लगता भी है तो सन्स आफ सोयेल जमीन के पुत्र को वरीयता न देकर बाहर से इंजीनियर और बड़े-बड़े अधिकारी लाकर के नियुक्त किये जाते हैं। यहां तक कि मजदूर लेवल के वर्कर भी अपने भर लेते हैं और वहां के

लोग देखते रह जाते हैं। उनको काम नहीं मिलता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कनक मुखर्जी) पीठासीन हुईं]

उपसभाध्यक्ष महोदया, यह एक समस्या है पूर्वी उत्तर प्रदेश की और बिहार के पिछड़ेपन की। जमीन पर जितना बोझ है उसको हमें वहां से धीरे-धीरे हटानी चाहिए। आप यह महसूस करेंगे कि लैंड लार्ड से ले कर के एग्रीकल्चरल लेबरर यह सब उसी पर मुनहसिर करते हैं जो वहां पर खेती है। खेती की माडर्न टैक्नोलोजी से यद्यपि विकास हुआ है लेकिन वहां अभी उतना विकास नहीं हुआ है। हम उससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेकर के वहां की हालत को सुधार सकें। इसलिए यह जरूरी होता है कि वहां पावर की व्यवस्था की जाए, छोटे-मोटे उद्योग धन्धों की व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को पावर प्राप्त हो और लोग छोटे-मोटे उद्योग धन्धे चला सकें। इसी तरीके से एजुकेशन की व्यवस्था हो। इन सारी बातों की जानकारी के लिए इन सारी बातों की व्यवस्था के लिए एक आयोग का गठन जरूरी है। मैं समझता हूं हमारे बहुत सारे साथियों के दिमाग में यह बात आयेगी कि पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए यह बातें क्यों कही जाती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समाज का सब से कमजोर हिस्सा होता है जो पिछड़ा हिस्सा या इलाका होता है उसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ध्यान देने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है ताकि प्लान के जरिये से उस क्षेत्र का विकास किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कल्पनाथ राय जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अपने सहयोगी और पुराने समाजवादी श्री कल्पनाथ राय जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की दरिद्रता, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और वहां का जो आर्थिक पिछड़ापन है उसको समाप्त करने के लिए साथ-साथ रोजगार के नये साधन पैदा करने के लिए जो प्रस्ताव में दिया है कि एक आयोग का गठन हो इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या महत्व रहा है इस देश की आजादी की लड़ाई में और साथ-साथ जो श्री जगदम्बी प्रसाद यादव जी ने अपना संशोधन प्रस्ताव दिया है कि मूल प्रस्ताव में बिहार शब्द जोड़ा जाए इसका भी मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, निर्धन हैं लेकिन बहुत ही आत्म सम्माननीय और स्वाभिमानी हैं। सन् 1857 में, अभी विकल जी चर्चा कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी की, जब इस देश की आजादी की लड़ाई, फर्स्ट वार आफ इंडिपेंडेंस हुई तो उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम किया। बलिया के मंगल पाण्डे ने मेरठ में उस लड़ाई का नेतृत्व किया और उसके बाद ही इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली—और आज भी वहां एक नीम का पेड़ है जहां सैकड़ों लोगों को 1857 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके साथ ही मैं माननीय सदन के कुछ सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 1857-58 में जिसकी मैंने चर्चा की, जिस जनपद से हमारे विद्वान मित्र श्री कल्पनाथ आते हैं, आजमगढ से उस आजमगढ का भी बहुत ज्यादा योगदान था। एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं डा. नंद लाल चटर्जी जिन्होंने अपने इतिहास की किताब में लिखा है:

> "It will be a news to many today that during the Mutiny of 1857-58 the town and even the countryside of Azamgarh became for several months. independent of British rule. The story of the exploits of the mutineers at Azamgarh is glorious for it unfolds an epoch of heroism and sacrifice which are unparalleled."

और इसका नेतृत्व किया था बिहार से आने वाले बाबू कुंवर सिंह ने और सभी लोगों ने मिलकर आजमगढ को आजाद कराया। ठीक इसी प्रकार 1922 में चौराचौरी कांड होती है गोरखपुर में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ा

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

था । उस आंदोलन में हिंसा हो गयी, गांधी जी ने उस आंदोलन को स्थगित किया लेकिन उस समय भी बलिया में अंग्रेजों के जमाने में कलक्टरी पर कब्जा कर लिया गया । मैं इन जिलों का नाम इसलिये ले रहा हूं कि ये 15 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं । इसके साथ ही साथ सन् 1942 में भी बलिया में अपना राज्य हुआ और चीतू पाण्डे के नाम को आज भी सारा देश बहुत ही गौरव से याद करता है । जहां तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों का सवाल है । 1885 के बाद इलाहाबाद में जब पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ । 1886 में उसके अध्यक्ष हुए इलाहाबाद के ही जो आगरा से जाकर वहां बस गये थे, पंडित अयोध्या नाथ कुंजरू, महामना मदन मोहन मालवीय चार बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, जवाहर लाल जी उनके पिता मोती लाल जी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन और श्रीमती इंदिरा गांधी । ये सब लोग उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही इनका कार्यक्षेत्र रहा है । इसके अतिरिक्त माननीय महात्मा गांधी जी जब इस देश में आये अफ्रीका के बाद और उत्तर प्रदेश में पदार्पण हुआ तो पहली बार पूर्वांचल, इलाहाबाद में 5 जुलाई 1896 में उनका आगमन हुआ था, दूसरी बार जब उत्तर प्रदेश में आये थे तो वाराणासी में गये 22 फरवरी 1902 को और जो 15 जिले इन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं उनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं इसलिए कि ये सारे जिले मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, वाराणासी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ, सुल्तानपुर और इलाहाबाद । 1981 की जनगणना के अनुसार सारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11 करोड 2 लाख थी और इन 15 जिलों की जनसंख्या 4 करोड़ 16 लाख 52 हजार है, यानि कुल आबादी का 37.57 प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहती है लेकिन इनमें से 79.8 प्रतिशत यहां के रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा कृषि है । और कृषि पर ही उनका जीवन आधारित है। लेकिन हालत क्या है ? आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सन् 1981 में जो जनगणना हुई, उसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता का प्रतिशत है, सब से कम है । आबादी में सब से ज्यादा, लेकिन साक्षरता में उसका प्रतिशत सब से कम ।

तो 1981 का जो आंकड़ा है जनगणना का, उसके अनुसार केवल 24.28 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में लिटरेट थे या साक्षर थे और आज भी वहां पर जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया, कृषि पर आधारित लोगों का जो प्रतिशत है वह 79.8 प्रतिशत है । इसका कारण है पूर्वी उत्तर प्रदेश में न सिंचाई के साधन हैं, न आवागमन के साधन हैं, न वहां पर रोजगार के लिए लोगों के लिए कोई विशेष सुविधा है और साथ ही साथ सब से ज्यादा वहां पर ऊसर जमीन है । इसलिए मैं एक पुस्तक की ओर सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस पुस्तक को लिखा है श्री ज्ञान स्वरूप भटनागर ने और इस पर प्रस्तावना है श्री कमलापति त्रिपाठी की क्योंकि 1961 या 1962 में एक बी. जी. पटेल आयोग गठित किया गया था केवल उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों के लिए । यह जिले हैं देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर, लेकिन उस समय श्री विश्व नाथ सिंह गहमरी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेता थे तथा लोक सभा के सदस्य थे, उनकी प्रस्तावना पर इस आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस पटेल कमेटी ने जितनी भी संस्तुति की, उनकी संस्तुति में से कोई भी संस्तुति आज तक लागू नहीं की गई है और उन्होंने जो चित्रण दिया है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, श्री ज्ञान स्वरूप भटनागर, उन्होंने वर्तमान प्रधान मंत्री के पिता श्री फिरोज गांधी को यह पुस्तक समर्पित भी की थी । इसमें लोक सभा के उद्धरण को देते हुए कहा गया है कि--

"उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन की दुखभरी शोधयात्रा का आरम्भ वास्तव में 1961 में गाजीपुर के तत्कालीन वयोवृद्ध कांग्रेसी लोक सभा सदस्य विश्व नाथ सिंह गहमरी के उस करुण भाषण से हुआ

था जिसके दौरान पूर्वी जिलों के निवासियों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए वह स्वयं फूट-फूट कर रो पड़े और उनके भाषण से प्रधान मंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू के सहित लोक सभा के अधिकांश सदस्यों की आंखों में भी ऐतिहासिक आंसू आ गये।''

उसके बाद जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पटेल कमेटी का गठन किया गया, लेकिन आज भी हालत यह है कि इस ओर--श्री कैलाशपति मिश्र भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि 1983-84 की जो पर कैपिटा इनकम है, जो बीस सूबे हैं हमारे देश में, इनमें उन्नीसवें नम्बर पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी 1983-84 में पर कैपिटा आय 1567 थी और उसके बाद अंतिम संख्या पर, यह बीसवें नम्बर पर आता है। बिहार जिसकी पर कैपिटा आमदनी 1184 है, यह हालत है आज हमारे उत्तर प्रदेश की, लेकिन यहां पर जितनी भी समय-समय पर बाढ़ आती है, गंडक, राप्ती, सर्यू नदी, साई नदी, गंगा, जमुना इन बाढ़ों को रोकने में भी हम असमर्थ रहे हैं। हर साल बाढ़ आती है और अभी इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का जो बजट भाषण है, उन्होंने स्वीकार किया है दैवी आपदाओं के संबंध में, इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि--

''दुर्भाग्यवश वर्ष 1985-86 में भी प्रदेश के 54 जनपद बाढ़, (कुल 57 जनपद हैं प्रदेश में, जिसमें 54 जनपद बाढ़) अतिवृष्टि तथा भूस्खलन से 34 जनपद सूखे से प्रभावित रहे हैं, जिनमें फसलों, मकानों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के साथ-साथ पशुओं और जनजीवन की भी काफी क्षति हुई।''

और इसी के साथ-साथ अभी जो नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई नवम्बर 1985 में, उसमें भी मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने भाषण दिया है, उसका मैं उद्धरण करना चाहूंगा क्योंकि तभी समस्या का निदान होगा जब समस्या के वास्तविक रूप में हम ज्ञान का प्रयास करेंगे और उसका चित्रण भी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने नेशनल डिवेलपमेंट कांउसिल की बैठक में किया है। उनके कहने का सार था कि उन्हें विरासत में एक ऐसे प्रदेश का शासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां पर कुछ भी नहीं है। सभी कुछ नए सिरे से करने की जरूरत है। 25 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों और जन जातियों की है जिसमें से 75 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे कराह रहे हैं। यह अफसोस ही नहीं है बल्कि शर्म की बात है कि प्रदेश में साक्षरता 25 प्रतिशत है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 36 प्रतिशत से भी अधिक है। इनमें से प्रदेश के वे साक्षर भी शामिल हैं जिन्हें सिर्फ अपना नाम ही लिखना आता है। प्रति एक लाख जनसंख्या पर अस्पतालों में केवल 46 शैय्याएं हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 74 की है। प्रति एक लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 22 पंजीकृत स्वास्थ्य अधिकारी हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 40 स्वास्थ्य अधिकारियों का है। एक लाख जनसंख्या की सिर्फ 63 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 100 किलोमीटर लम्बी पक्की सड़कों का है। अभी जो रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें एक किलोमीटर भी नई रेल लाइन बिछाने का न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे गोंडा हो, चाहे फैजाबाद हो, इन सब में रेलों की लाइनों का जाल नहीं बिछा हुआ है। बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि आजमगढ़ को बड़ी लाइन से जोड़ा जाए, मऊ को बड़ी लाइन से जोड़ा जाए, बलिया को और बस्ती को बड़ी लाइन से जोडा जाए। भटनी से ले करके वाराणसी तक के लिए प्रस्ताव भी हुआ लेकिन आज तक यह काम चल रहा है और वर्तमान बजट में केवल एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि करीब-करीब 67 करोड़ की यह योजना है। यह दुर्दशा है आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की। श्री कल्पनाथ राय ने और श्री रामचन्द्र विकल ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया और रिपोर्ट में लिखी थी कि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो दरिद्रता है और जो कृषि के क्षेत्र में बहुतायत में लगे हुए लोगों

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

के रहने के कारण भी वहां पर यह हालत है। वहां पर जाति के कुछ ऐसे लोग हैं मैं उनका नाम लेना चाहूंगा जैसे भूमिहार क्षेत्रीय या पंडित या ब्राह्मण, यह पटेल आयोग ने लिखा है कि जातिगत आधार पर ये लोग कृषि के पेशे को खेत में जा करके हल चलाने में अपनी बेइज्जती समझते हैं और इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं। यह कारण भी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीबी का है। आज हालत यह है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और भी छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं जैसे चूड़ी बनाने का कारखाना हो या मऊ आजमगढ़ में बुनकर लोग हैं, बनारस भदोई के पास दरी बनाने वाले लोग हैं, टीन के कनस्तर बनाने वाले लोग हैं या एलुम्यूनियम के बरतन का रोजगार करने वाले लोग हैं इनके लिए कोई भी साधन लघु उद्योग के लिए या कृषि उद्योग के लिए नहीं है। अभी शुकदेव प्रसाद जी चर्चा कर रहे थे कि सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा कारखाना नहीं है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के कारखानों को कोई सहायता न देना, इनके लिए सरकार की ओर से कोई विशेष सुविधा का इंतजाम न होने के कारण भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीबी का कारण है। क्योंकि जब कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ होगा किसी क्षेत्र में गरीब लोग अधिक होंगे तो जब तक सरकार के द्वारा वहां कोई विशेष सहायता की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक उस क्षेत्र की और उस पिछड़े हुए इलाके की कोई तरक्की नहीं होगी। मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और मुख्य मंत्री जी से इस बात को पूछा भी था कि जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं उनके लिए योजना बना करके उत्तर प्रदेश सरकार विशेष वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजती है, क्या ठीक उसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी कोई विशेष योजना बना करके केन्द्र सरकार के पास भेजी गयी है या नहीं? लेकिन उसका उत्तर मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तो योजना बना कर भेजी है लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके हैं इनके लिए कोई भी योजना बना कर नहीं भेजी है। इसलिए सदन के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस सिलसिले में विशेष योजना बनानी चाहिए विशेष अर्थ की मांग को रखना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कम से कम 15 पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, यहां के लोग किस प्रकार से गरीबी को दूर कर सकें, किस प्रकार अपनी निर्धनता से मुक्ति पा सकें, किस प्रकार अपनी निरक्षरता को दूर कर साक्षर बन सकें।

एक बात और अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि यह जितनी भी बाढ़ की समस्या उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती है, उसका कारण यह है कि हम आज तक बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे हैं। मैंने शुरू में निवेदन किया था कि हर साल वहां बाढ़ आती है, गांव के गांव बह जाते हैं, खेत के खेत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना चाहिए और जितना भी अधिक धन हो, वह उत्तर प्रदेश सरकार को या योजना आयोग के जरिए जो बाढ़ आयोग है, उनको उपलब्ध कराके इस बात का इंतजाम करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के गांवों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष जो बाढ़ आती है और लाखों के लाखों लोग इसके शिकार हो जाते हैं, अकाल के शिकार हो जाते हैं, भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, इसका स्थाई समाधान निकाला जाय। बाढ़ हर साल आती है, अकाल के नाम पर, सूखे के नाम पर, बाढ़ के नाम पर सरकार को सहायता दी जाती है, वहां पर टेस्ट वर्क शुरू किए जाते हैं, लेकिन बाढ़ से हर वर्ष लोग ग्रसित न हों, बाढ़ से पीड़ित न हों, इसके लिए केन्द्र-सरकार को विशेष उपाय करने चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से गरीबी दूर होने वाली नहीं है और इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है, उत्तर प्रदेश की जो गरीबी है और उत्तर प्रदेश की जो दरिद्रता है, वह तभी दूर होगी, जब केन्द्र सरकार इसके लिए खुले हाथों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करेगी और इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी, जिसमें कि वहां के लोगों की दरिद्रता दूर हो, वहां पर कुटीर-उद्योग लगें, वहां पर लघु उद्योग स्थापित हों उनके लिए सिंचाई के साधन, उनके लिए

है, उनके लिए सिंचाई के साधन, उनके लिए आवागमन के साधन, उनके लिए पीने के पानी के साधन, उनके खेतों के लिए पानी पहुंचाने के साधन उपलब्ध कराए जायं और सरकार इसको प्राथमिकता के आधार पर कराने के लिए ध्यान दे।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार के सिलसिले में जो बातें कही गयी हैं और जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि बिहार की पर-कैपिटा-इन्कम उत्तर प्रदेश से भी कम है और यह बात भी सही है कि अगर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को इसमें से हटा लिया जाय तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत बिल्कुल बराबर होगी। इन दोनों की पर-कैपिटा-इन्कम हिन्दुस्तान में जितने भी सूबे हैं, उनमें सबसे कम होगी।

अन्त में, पुनः कल्पनाथ जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चाहूंगा कि इस माननीय सदन में सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनका आदर करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से आज ही घोषणा की जाए कि एक आयोग का गठन किया जायगा आए दिन आयोग गठित होते ही रहते हैं, तो कम से कम इस मामले में, जबकि उत्तर प्रदेश में, जो इस देश में सबसे बड़ा सूबा है, उसके सबसे बड़े हिस्से में 15 जिलों में रहने वाले लोगों की तरक्की के लिए, उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यह जो कल्पनाथ जी का सुझाव है और इन्होंने जो प्रस्ताव यहां रखा है, उसके संबंध में पुनः आपसे आग्रह करूंगा सरकार से कि आज ही घोषणा करनी चाहिए, कि इस संबंध में आयोग का गठन किया जाएगा और वह अपनी छह महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिससे इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या का। धन्यवाद।

श्री सुधाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक विपन्नता की ओर हमारे मित्रों ने ध्यान आकर्षित किया है और प्रस्ताव कल्पनाथ राय जी ने उपस्थित किया है। यह चर्चा जो आज सदन में हो रही है, जब से मैं बच्चा था, तब से यह चर्चा बराबर सुनता चला आया हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निर्धन है और उस निर्धनता के मूल में जब हम जाते हैं तो उस स्थान के लोग अगर दोषी होते, तो शायद इतनी पीड़ा नहीं होती और इतनी चिन्ता नहीं होती, जितनी कि आज हो रही है। हमारी उर्वरा भूमि है। शायद भारत का या संसार का सबसे प्राचीन नगर काशी है जिसके इर्दगिर्द पूर्वी उत्तर प्रदेश बसता है। विज्ञान के क्षेत्र में इस क्षेत्र ने राष्ट्र को जो अविदान दिया है अनादि काल से उसको अगर मिटा दिया जाय तो इस देश के पास कुछ सत्व की चीज नहीं बचती। बुद्ध को वहां प्रकाश मिला, शंकराचार्य को वहां प्रकाश मिला, रामानन्द जैसे मनीषी वहां पर हुए। कबीर जैसा विद्रोही जिस क्षेत्र में रहा, गोरख जैसा राष्ट्र को जगाने वाला जिस क्षेत्र में हुआ, जिस क्षेत्र में ऐसे-ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारी रचना की और ऐसी रचना की कि देश को ज्ञान की ऊर्जा मिलती रहे वहां आज यह स्थिति हो यह दुर्भाग्य की बात है। ज्ञान की ऊर्जा देने में ही वे आगे नहीं रहे, विद्रोह का भी उन्होंने नेतृत्व किया।

आज उत्तर प्रदेश में दो बड़े विश्वविद्यालय हैं अलीगढ़ और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पहला दान—उसकी कल्पना काशी में हुई और उसको पहला दान काशी के एक ब्राह्मण ने 50 हजार रुपए का दिया। मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाया। 1857 के आन्दोलन में काशी का योगदान रहा ही है, उसके पहले भी चैत सिंह ने अंग्रेजों को रोक दिया था और वारेन हेस्टिंग्ज को छिप कर भागना पड़ा। स्वतंत्रता के आन्दोलन के हर क्षेत्र में काशी का योगदान है ही।

अभी मालवीय जी कह रहे थे क्या एनी बेसेंट के बिना भारत का इतिहास पूरा हो सकता है, क्या डा. भगवान दास के बिना देश पहचाना जा सकता है, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, क्या सम्पूर्णानन्दजी भुलाए जा सकते हैं, जब समाजवाद की चर्चा की जायगी तो क्या नरेन्द्रदेव जी को नकार देंगे, क्या भारत की संस्कृति का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें प्रेमचन्द और प्रसाद नहीं होंगे।

इतना ही नहीं, यहां के गरीबों ने बहुत से महानगरों को श्रीसम्पन्नता दी है। रिक्शा ढोते हैं, बोझा उठाते हैं और बैल का जीवन जीकर लोगों को श्री और सम्पन्नता दे रहे हैं।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

इतना ही नहीं, इन गरीबों ने मारीशस, ट्रिनिडाड, जौका जैसे देशों को श्रीसम्पन्न किया है। लगता है कि हमारे पास पुरुषार्थ है, हमारे पास शस्य-श्यामल भूमि है, हमारे पास पानी है, हमारे पास पहाड़ है और वही एक ऐसा स्थान है उत्तर भारत का जहां विंध्याचल गंगा को स्पर्श करता है और देश के दोनों भागों को जोड़ता है। ऐसे स्थान के लोग तृषित, कापित और प्रताडित हों तो समझ में नहीं आता। उसके मूल में क्या कारण है जब उनको ढूंढा जाता है तो लगता यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने विद्रोह किया था--कैसा शहर देश के अन्दर था। और शहर ऐसे हैं जहां लोग जीने के लिए जाते हैं, लेकिन यहां सारे संसार के लोग आते हैं, मरना सबको है लेकिन मरना भी लोग काशी में पसन्द करते थे----लगता है कि हमने जो सामाजिक क्रान्ति की, हमने जो चेतना का जयगान किया और जिसके माध्यम से हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया उसका अंग्रेजों ने हमसे बदला लिया और इसीलिए अंग्रेजों के समय में वहां बिल्कुल विकास नहीं हुआ। आशा नहीं थी कि स्वतंत्र भारत में उस परम्परा को ढोया जायगा, किन्तु वह परम्परा बराबर ढोई जाती रही। आज भी हमारे यहां ऐसे-ऐसे कारीगर हैं जिनके हाथों से बनी हुई साड़िया पहनकर कुरूप औरत भी सुन्दर ही बन जायं। आज हमारे कालीन सारे संसार में जाते हैं और 70-80 करोड़ रुपया कम से कम फारेन एक्सचेंज कमाते हैं। लेकिन जहां हम फारेन एक्सचेंज कमाते हैं उन सड़कों पर चलना भी बड़ा मुश्किल है और अगर कोई गर्भवती औरत हो तो रिक्शा और बस के धक्के से उसे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। वह मर भी सकती है या शिशु को सड़क पर ही जन्म भी दे सकती है। यह जिले एक दूसरे से मिले हुए थे किन्तु छोटी लाइन और बड़ी लाइन में परिवर्तन करने से ऐसा हो गया कि अब गोरखपुर बनारस से कट गया। गाजीपुर तक या पटना तक हम बड़ी लाइन से आ सकते हैं और उसके बाद छोटी लाइन है। अगर हम गोरखपुर रेल से जाना चाहते हैं तो दो जगह हम को गाड़ी बदलनी पड़ेगी और भगवान भरोसे ही हम वहां पहुंच पायेंगे। तो हम लोग जो जुड़े हुए थे, हम गरीब आपस में बैठ कर एक दूसरे का सुख दुख सुन सकते थे उस को भी आप ने काट दिया और मालवीय जी ने कहा था कि अगर 67 करोड़ रुपया देना है तो वह 67 वर्ष में ही मिलेगा तो उस समय तक तो हम और आप कोई भी नहीं रह पायेंगे। (व्यवधान) काशी ने एक पुल का शिलान्यास गंगा पर इन्दिरा जी ने किया था और वह इस लिये किया था कि वहां हमारा उस से कुछ आर्थिक विकास होगा। हम को पुलों की जरूरत नहीं है लेकिन हमारा आवागमन कुछ सुविधाजनक हो जायगा क्योंकि घंटों वहां लोगों को रुके रहना पड़ता है और राष्ट्रीय सम्पदा का नुकसान होता है। तो उस के बाद 1974 से आज यह 1986 आ गया और 12 वर्ष बाद भी वह पुल नहीं बना।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Please make your speech short. There are so many speakers. We have to finish at 4.30.

श्री सुधाकर पाण्डेय: तो विकास के जितने काम हमारे यहां हुए वे भी पूरे नहीं हुए और कागजों पर ही पड़े हैं। आप ने किसी और को नहीं कहा लेकिन मैं बहुत कम बोलता हूं, मुझे ही जल्दी समाप्त करने के लिए कह रही हैं। यहां भी सरकार ने सोचा कि अगर यह गरीब बढ़ जायेंगे तो यह और विकास की मांग करेंगे। हम भीख नहीं मांगते। हमारे पास पुरुषार्थ है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास शक्ति है, हम टैक्स भी देते हैं और त्याग और बलिदान की बात होती है तो हम सब से आगे रहते हैं। किन्तु आप हमारे भोजन की व्यवस्था करेंगे या नहीं। मैं एक दिन नोगढ़ गया था। वहां हम ने बच्चों से कहा कि पढ़ो। वह बच्चे कहते हैं कि जब हम को तनख्वाह नहीं मिलेगी हम पढ़ेंगे नहीं। 8 वर्ष का बच्चा कहता है कि तनख्वाह नहीं मिलेगी तो पढूंगा नहीं। यहां आप कहते हैं कि समय नहीं है। इस पार्लियामेंट के पास वहां की बात के लिये समय नहीं है। जहां जीवन जल रहा है, भुन रहा है, उस की बात के लिये यहां समय नहीं है। मुझे आपने कहा कि समय नहीं। मैं जलभुन रहा हूं। गरीबी को बलि पर चढ़ाने से जो आग पैदा होती है उस में बड़े बड़े सम्राट धूलधूसरित हो जाते

है और व्यक्तियों की चर्चा तो बहुत दूर की बात है । हम कोई बड़ी बात नहीं चाहते । पूर्वी उत्तर प्रदेश को हम सोने का नहीं बनाना चाहते । हम चाहते हैं कि उस में सड़कें बनें ताकि हम आ जा सकें । तीन, चार मैं एकड़ पर जो आप का मापदंड हो उस के अनुसार हमें वहां ट्यूब वेल दीजिए, हमारी नहरें ठीक कराइये और हमारे जो उद्योग धंधे हैं उन के विकास की बात करिये । लकड़ी के खिलौने बनारस में सब से अच्छे बनते हैं । आज जंगलों में वह लकड़ी नहीं मिलती है । वह मध्य प्रदेश में मिल रही है। हजारों आदमी लकड़ी के खिलौने बना कर रोजी कमाते थे और वह खिलौने सारे संसार में जाते हैं, लेकिन आज उन के लिये कारीगरों को लकड़ी नहीं मिलती । रा मैटीरियल नहीं मिलता । कहा गया कि कोआपरेटिव बना दीजिए । वह भी बना दी गयी लेकिन लकड़ी न मिलने से खिलौने नहीं बन सकते। वह कहां जायें अब स्वर्ण मंदिर में जब सोने का कलश चढ़ाने की बात हुई तो उस के लिये काशी से कारीगर बुलाये गये । तो यह कला जो हमारी प्राचीन कला है वह एक दो दिन में नहीं बन पायी है । वह हजारों वर्ष की तपस्या कर के प्राप्त की गयी है । भारत के कलाकारों को जो यह मूर्तमान ज्ञान है, वह भले ही निरक्षर हो, लेकिन उनको यह पैतृक कला मिली है । आज हमारे गांवों के जो स्कूल हैं वह इतनी बुरी हालत में हैं कि वहां भैंसे भी नहीं बांधी जाती, लेकिन वहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वह हमारे बच्चे हैं कि जिनसे हम आशा करते हैं कि वे एक दिन हमारे देश के कर्णधार बनेंगे । आज हमारे यहां अस्पताल में कोई घायल आता है तो उससे कहा जाता है कि पट्टी ले आइए, वहां अस्पताल में पट्टी भी नहीं मिलती । जब वह पट्टी लाता है तब उसका इलाज होता है । तो यह जो अभाव है, यह जो कमी है, यह जो दरिद्रता है, उसकी तरफ ध्यान सबका जाना चाहिए । कागज पर सब का ध्यान जाता है । आयोग बनेगा कि नहीं यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह तो उसी प्रकार का प्रस्ताव है जैसा कि स्पेशल मैंशन का होता है, जो आज को दिन भी है, अगर ध्यान उधर गया भी, अगर उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा । कोई कल-कारखाना वहां नहीं । एक कारखाना वहां खुला तो वह इसलिए कि संपूर्णानंद जी चीफ मिनिस्टर थे । इसके बाद कोई कारखाना कहीं नहीं खुला । छोटे छोटे कारखाने भी नहीं खुले । ग्रामोद्योग भी नहीं खुले और कोआपरेटिव हम लोगों की जो वहां है वह गरीब के यहां जाती है और उसका शोषण करके बैठ जाती है । उसको देखने वाला कोई नहीं है । तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें । इस प्रस्ताव की मंशा यह है कि उनकी जो गरीबी दूर करने के लिए जो आप कर सकते हैं, वह करें । उनमें पुरुषार्थ है, उनमें प्रतिभा है, उनमें जीवन की ललक है, देश के लिए उन्होंने योगदान किया है और आगे अधिक योगदान वह करना चाहते हैं ।

इसलिए इस प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं समर्थन करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश जो भारत की अस्मिता की पहचान सदा से रहा है, इसके लिए जो कल्याण का काम करेगा उसका सदा कल्याण होगा ।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी : मैडम वाइस चेयरमैन महोदया, जिस प्रस्ताव को श्री कल्पनाथ राय जी ने सदन के सामने रखा है और जिसमें संशोधन करते हुए श्री यादव जी ने और श्री दरबारासिंह जी ने कहा कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही सीमित न रहे बल्कि देश के जो पिछड़े इलाके हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए सारे देश पर विचार किया जाएगा, मैं इसका स्वागत करता हूं ।

जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, देश के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और दूसरे प्रांत ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, ये सब पिछड़े इलाकों में माने जाने चाहिए । कल्पनाथ राय जी ने इस प्रस्ताव को लाकर सारे देश के जितने पिछड़े इलाके हैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश के बारे में वहां के सदस्यों ने तफसील से कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता । लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने पिछड़े इलाके हैं, राजस्थान,

[श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी]

उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब के बारे में केन्द्रीय सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि यह पिछड़ेपन का कारण क्या है और कौन कौन से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। अब तक हमने 5-6 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर ली हैं और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम सोच रहे हैं कि इसको अमल किया जाए, तो मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि अब तक पूरी हुई 5-6 योजनाओं के बाद भी कितने इलाके पिछड़े हुए हैं, उनमें कितनी वृद्धि हुई है और 7वीं योजना में आप क्या करने वाले हैं। जैसा कि सदस्यों ने कई कारण इसके लिए रखे, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस ढंग से इसको आगे बढ़ाने और पिछड़ेपन को दूर करने की बात सरकार सोच रही है, यह बतायें। असल में सोचना यह है कि यह पिछड़ापन है क्यों? किस इलाके को, किस प्रान्त को, किस जगह को पिछड़ा कहा जाता है क्या इसके बारे में कुछ सोचा है? आमतौर पर वे इलाके, वे प्रान्त जहां सिंचाई का कोई इन्तजाम न हो, नदी-नाले न हों, कोई नहर का इन्तजाम न हो, सड़कें न हों, वहां के लोगों के लिए रोजगार के साधन न हों, पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई हो, उनको कोई रोजगार पहुंचाने का साधन न हो, वहां रह कर वे काम न कर सकते हों, काम नहीं मिल पाता हो, इन सब चीजों को देखकर, ऐसे सब प्रांतों के बारे में सरकार को योजना बनानी चाहिए। मैं तफसील में न जाते हुए उदाहरण के लिए एक प्रान्त का नाम लेता हूं जिसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी भी रखता हूं। वह है आन्ध्र प्रदेश के प्रान्त। रायलसीमा तेलंगाना हमेशा पिछड़े प्रान्त रहे हैं। आन्ध्र के कुछ जिलों में एक और जिला है श्रीकाकुलम, यह भी पिछड़ा इलाका है। खासकर तेलंगाना के इलाके में महबूब नगर, आदिलाबाद के इलाके ऐसे हैं जहां कोई पानी का या सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है। वहां कोई नहर वगैरह भी नहीं है और न उद्योगीकरण की कोई योजना है। वहां बेरोजगारी भी बहुत है। महबूब नगर के बारे में इस सदन में भी कल एक सदस्य ने कहा था कि ठेकेदार लोग हैं वे वहां के गरीब लोगों को दूर-दूर जगह पर ले जाते हैं। यह सिर्फ आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में है। यहां के लोगों को, गरीब लोगों को विदेशों में ले जाते हैं। मजदूरों को थोड़ा सा लालच देकर विदेशों में ले जाते हैं। इस जिले के मजदूरों का नाम भी पालमूर मजदूर पड़ गया है। सारे देश में जो ठेकेदार हैं वे उन गरीब मजदूरों को कुछ पैसा दे देते हैं और उनको ले जाकर वहां छोड़ देते हैं। ये एक किस्म के बन्धुआ मजदूर बन गये हैं। यह समस्या केवल महबूब नगर की ही नहीं है यह समस्या सभी पिछड़े इलाकों में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार या रायलसीमा में यह समस्या है। जहां मुसीबतें हों, जहां अकाल पड़ता है, जहां सूखा पड़ता है ऐसे इलाकों में लोगों को रोजगार तक नहीं मिल पाता। वहां कारखाने नहीं हैं। कारखाने न होने की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। दूसरी जगहों पर काम की तलाश करनी पड़ती है। इन तमाम चीजों को सरकार को मद्देनजर रखना चाहिए और पिछड़ेपन की समस्या को दूर करना चाहिए। तेलंगाना के कुछ जिलों का मैंने जिक्र किया और उनमें से रायलसीमा का उदाहरण भी दिया। वहां पर हमेशा सूखा पड़ता है। तीन साल से सूखा पड़े रहने के कारण वह सारा इलाका तबाह हो गया है, नष्ट हो गया है। वहां लोगों को परेशानी है, रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में वहां की सरकार ने एक योजना बनाई है। इस सूखेपन को दूर करने के लिए एक योजना बनाई है। मद्रास शहर के लोगों की पीने के पानी की समस्या दूर करनी होगी। यह योजना है तेलुगु-गंगा। इस तेलुगु-गंगा को पूरा करने से न सिर्फ मद्रास शहर में रहने वालों को पानी मिल पायेगा बल्कि जो रायलसीमा है जहां हर साल सूखा पड़ता है वहां इससे पानी पहुंचा कर किसानों को राहत दी जा सकेगी। तेलुगु-गंगा योजना केन्द्रीय सरकार के सामने है। उनकी अनुमति के लिए पेश की गयी है लेकिन आज तक उसको अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। मैं सरकार से चाहूंगा कि ऐसे जितने प्रोजेक्ट हों, जैसे तेलुगु-गंगा प्रोजेक्ट, वंशधारा प्रोजेक्ट ये बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके पूरा होने से न सिर्फ उस प्रान्त की अभिवृद्धि होगी बल्कि सारे देश की अभिवृद्धि होगी। सारे देश को फायदा होगा। चाहे आन्ध्र का प्रोजेक्ट हो, मद्रास का प्रोजेक्ट हो, बिहार का या उत्तर प्रदेश

का प्रोजेक्ट हो इन सभी प्रोजेक्टों को सरकार को नेशनल प्रोजेक्ट की नजर से देखना चाहिए और उसको अनुमति देने में सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार को इसको सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए । हम देखते हैं बहुत सी योजनाएं हैं जैसे (इरीगेशन की, हाइड्रो इलेक्ट्रीकल प्रोजेक्ट की योजनाएं हैं) । अभी हालत यह है कि पांच साल में जो योजना तैयार होनी चाहिए, कम्प्लीट होनी चाहिए उसको 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि जिस योजना पर दो सौ करोड़ या तीन सौ करोड़ रुपये लगने चाहिए उस पर खर्चा बहुत बढ़ जाता है और वह एक हजार करोड़ और 12 हजार करोड़ रुपयों तक पहुंच जाता है । पन्द्रह या बीस साल गुजर जाने के कारण उसकी कीमत में 50 फीसदी की वृद्धि हो जाती है । इससे हमारे देश का नुकसान होता है । होना यह चाहिए कि जब कोई योजना पांच साल के लिए बनती है तो उसको पांच साल में पूरा हो जाना चाहिए और इस सुझाव पर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए ।

इसी तरीके से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं । आप जानते हैं कि नागार्जुन सागर एटोमिक पावर स्टेशन के बारे में एक कमेटी ने सिफारिश की है । उसके बारे में हमने यहां पर भी कई बार कहा है । ऐसी जितनी भी प्रोजेक्टस हैं, चाहे वह इरीगेशन प्रोजेक्ट हो, हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, उनको अपने समय के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए । इन योजनाओं के पूरा होने से उन इलाकों का पिछड़ापन दूर होगा । अभी हालत यह है कि इन पिछड़े इलाकों में लोगों को काम नहीं मिलता है। इस प्रस्ताव के जरिए श्री कल्पनाथ राय जी ने यह मांग की है कि एक आयोग की नियुक्ति की जाये । उस आयोग का काम बड़ा अहिम है । इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार तत्काल एक आयोग नियुक्त करे जिसमें योजना आयोग के सदस्य हों और जिसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश हो और यह आयोग उस क्षेत्र के पिछड़ेपन के विद्यमान कारणों की जांच करे और उसकी आर्थिक प्रगति की गति को तेज करने के लिए उपचार उपायों का सुझाव दे और छः महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । इसमें आगे कहा गया है कि इस बीच इस क्षेत्र के पिछड़ेपन की गम्भीरता तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कच्चे माल तथा रोजगार के अवसरों जैसे संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए एक त्वरित कार्यक्रम तैयार किया जाये। इसमें जो सुझाव दिये गये हैं उनको सरकार को छः महीने में पूरा करना चाहिए । यह बड़ा अच्छा सुझाव है । मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि सरकार को हमारे देश में जो पिछड़े इलाके हैं, चाहे वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या आन्ध्र प्रदेश के इलाके हों, उनके विकास के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए ।

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश): आदरणीय मैडम, श्री कल्पनाथ राय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । यह एक जरूरी प्रस्ताव है । हमने अपनी आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमारे देश में जो गरीब इलाके हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको हमें ऊपर उठाना है । हमने यह सपना देखा था कि हम इन लोगों की गरीबी मिटाएंगे । वह सपना हमारा पूरा होने जा रहा है । लेकिन आज जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारे जो पिछड़े इलाके हैं उनमें उतनी तरक्की नहीं हो पाई है जितनी तरक्की होनी चाहिए तो हमें यह कहना पड़ता है कि इस तरह का एक आयोग पूरे भारतवर्ष के लिए बनना चाहिए । जितने भी हमारे पिछड़े इलाके हैं उनका हम आकलन करें और उनको ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बनायें । मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं । जैसे बस्तर का इलाका, झाबुआ, रायगढ़ और सरगुजा इत्यादि । यहां पर लोगों को दोनों वक्त का खाना मिलना कठिन है । इनके तन पर पूरा कपड़ा नहीं है, अस्पताल नहीं है, आवागमन के साधन, रहने के मकान नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों की बात कही गई है उसी तरह से सरकार देश भर के पिछड़े इलाकों के लिए योजनाएं बनायें । हमारे प्लानिंग कमीशन एवं भारत सरकार को, पिछड़े इलाकों के बारे में यह तय

[ठाकुर जगतपाल सिंह]

करना चाहिए कि सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका कौन है ? जो सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका है उसको सरकार को गरीबी से मिटाने के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये । हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं । खेती के अंदर आप सभी जानते हैं कि टाइम फैक्टर मूल्य होता है जो कि इंडस्ट्री में नहीं होता । खेतों में अगर पानी आज चाहिए तो आज ही देना होगा । जब खाद चाहिए तो समय पर ही खाद देना होगा । क्या उन इलाकों में हम समय पर इन चीजों को दे पाते हैं ? यदि नहीं तो गरीबी कैसे मिटेगी ? गरीबी कैसे मिटती है, गरीबी मिटती है जब उस इलाके में गरीबी मिटाने के साधन दिये जायें । क्या उन इलाकों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाई है ? अगर बढ़ाई भी है तो क्या किसानों को जरूरत के अनुसार पानी मिल रहा है ? मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और न उन बातों को दोहराना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों ने कही है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग में कुछ बुनियादी गलतियां हैं । अन-प्लान्ड एकानामी, अन-प्लान्ड एजूकेशन, अन-प्लान्ड इम्पलाईमेंट । आज हमारी जो बुनियादी गलती है वह हमारी शिक्षा पद्धति की है । चाहे पिछड़े हुए इलाके हैं लेकिन उन इलाकों में भी डिग्री कालेज आप खोल देंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि उनको इम्पलाईमेंट कहां मिलेगा ? पिछड़े इलाकों में जो नेचुरल है उनको आपको डेवलप करना होगा, वहां पर जो कमियां हैं उन्हें पूरा करना होगा । आज एम0 एस0 सी0 फर्स्ट क्लास फर्स्ट लड़का आई0 पी0 एस0 में जा रहा है, आई0 ए0 एस0 में साइंटिस्ट जा रहा है, एक ला ग्रेजुएट जो लीगल ब्रेन है वह कोआपरेटिव का इंसपेक्टर बन रहा है । अन-प्लान्ड एजूकेशन, अन-प्लान्ड इम्पलाईमेंट से प्लान्ड रिजल्ट नहीं आ सकते । यही कारण है कि आज देश के अन्दर जो प्लानिंग है उतना सफल नहीं हो रहा है, उस प्लानिंग को हमें बदलना होगा, शिक्षा की पद्धति में बहुत कुछ कमियां हैं ।

अंत में मैं श्री कल्पनाथ राय जी को, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, उनको बधाई देना चाहता हूं । लेकिन साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, आप यह कहें कि पूरे हिन्दुस्तान में जो सबसे पिछड़े इलाके हैं, उनके लिए कमीशन बनाया जाये, उन्हें पहले उठाया जाय । उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से ज्यादा हमारा मध्य प्रदेश का इलाका गरीब है । मध्य प्रदेश के अन्दर इतनी गरीबी है जितनी कि कहीं नहीं है ।

श्री राम चन्द्र विकल: आप यू. पी. के भी हैं ।

ठाकुर जगतपाल सिंह: मैं यू.पी की ही बात कर रहा हूं ।

मैडम, अंत में एक जरूरी बात कह दूं । आप याद रखें कि अगर आपके सामने पिछड़े हुए इलाकों को नहीं उठाया तो उन इलाकों मे एक नई क्रांति एक नया रिवोल्ट होगा । शोषित जब शोषण के प्रति कांसेस होता है तो रिवोल्ट हुआ करता है, क्रांति हुआ करती है । इसलिए जरूरी है कि सरकार जो बढ़ते हुए इलाके हैं उनको रोके और जो इलाके नहीं बढ़ रही हैं उन्हें उठाये । नहीं तो रीएक्शन होगा, उन इलाकों में जो गरीबों के इलाके हैं । गरीब की न जाति होती है, न धर्म होता है, जब गरीब आदमियों को खाना नहीं मिलता तो उसके अंदर एक भूख की ज्वाला निकलती है और वह ज्वाला न धर्म देखती है, न जाति देखती है । मैडम, इस मामले में (समय की घंटी) मुझे आप समय दें मैं आपकी ही बात कह रहा हूं । इसलिए आप मुझे थोड़ा समय और दें । मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछड़े हुए इलाकों में एक आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है और उस आग में पानी गिरना बहुत जरूरी है और वह पानी होगा उस इलाके के अन्दर तेजी से विकास करना । उस इलाके के अन्दर किसानों की पैदावार बढ़ाना और पैदावार के उचित दाम दिलवाना । आज आप देखें मंडियों में क्या-क्या हो रहा है ? मैडम मैं एक बात कहकर खत्म कर दूंगा । जो छोटे किसान हैं, उनकी इनपुट्स के दाम बढ़ते जाते हैं और उनको अपने माल के दाम इतने नहीं मिल पाते हैं । इसके लिये आवश्यक है कि जो मंडियां हैं, जो विलेज में गांव के बाजार लगते हैं, उनसे मंडियों को

आप लिंक करिये तभी उन्हें अपने माल का फेयर प्राइस मिल सकेगा वरना उन्हें फेयर प्राइस नहीं मिल सकता ।

मैडम आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । अंत में मैं कल्पनाथ राय जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वे इस प्रस्ताव को विचार के लिए लाए हैं, वापस तो इसको लेंगे ही यह मैं जानता ही हूं, लेकिन उन्होंने एक अच्छे विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Mr. Chitta Basu.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Madam, my name is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): All right. Please take only five minutes.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I will not take more than five minutes. Madam Vice-Chairman, I rise to support the Resolution moved by Shri Kalpnath Rai. Madam, there are many backward districts, many places, many pockets in various States which are backward. But a start has to be made somewhere. Therefore, I feel, what Mr. Kalpnath Rai has said is the starting point of that process. Shri Darbara Singh spoke about this. Just now, our friend from Madhya Pradesh mentioned about such pockets. This morning, Madam, I also spoke about Jammu and Kashmir and pointed out that out of Rs. 30,000 odd crores invested in the public sector, only Rs. 7 crores are invested in the State of Jammu and Kashmir. But if one limb of the body is weak or ill the whole body will be aching. So, a start has to be made. I feel that Shri Kalpnath Raiji has mentioned about the districts of Basti, Azamgarh, Deoria, Gorakhpur, Bahraich, Balia, Jaunpur, Mirzapur, Rampur and Varanasi. They almost have a total population of 6 crores. This is an irony of fate that Uttar Pradesh which has a population of 12 crores is one single province and this is equal to the entire countires of the Western world. I do not know how a State like Uttar Pradesh can be treated as one State and that is why there has been a demand of Purvanchal by the people of these districts. There is a historical background also. In the 1857 war and other wars about which Mr. Malaviya has also said, Chittu Pande waged a war against the British. They wanted to keep Eastern U.P. backward for that reason. It is not the policy of the Congress to keep Eastern U.P. as backward so that they remained illiterate because the Congress stands for socialism and equality for all. Now that is the main point of my speech that there is a constitutional guarantee. There is a constitutional provision under article 340 which reads as under and I quote:

> "Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes."

It is exactly like the Resolution put forward by Mr. Kalpnath Rai. It states under article 340(1) as under:

> "The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission."

In the light of a clear provision in the Constitution of India under arti-

[Shri Ghulam Rasool Matto]

cle 340 I think a start must be made by the Planning Commission and to request the President to appoint a Commission as suggested by Shri Kalpnath Rai under article 340 so that the backwardness of the State is removed.

With these observations I commend the Resolution of Shri Kalpnath Rai.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Madam, the question which we are discussing in the form of the Resolution, I may make out at the outset, does not relate to a particular State but raises a very fundamental question of the socio-economic conditions of our country even after the completion of six plans in our country. The major question that has been posed is the question of regional disparities and regional imbalance. I have got certain figures which suggest very pitiable condition in certain parts of the country. To be very brief I only refer to one figure because I see or I expect that the hon. Minister incharge of Planning would be here to take part in this debate. Only for his attention I quote certain figure which is the index of real per capita income of States/Union Territory at 1970-71 prices with all-India or national average of per capita income at 1970-71 prices as 100. The latest figure available is of 1983-84. Madam, I shall mention about Manipur, Tripura, Uttar Pradesh and Bihar. Bihar comes to 58.3, Uttar Pradesh comes to 71.2, Manipur comes to 73.4 and Tripura comes to 82.6—i.e. much below the national average.

Now I want to refer particularly to this region of the country—the Eastern region. Mr. Malcom S. Adiseshiah a renowned economist of our country who happened to be a Member of this House also, has, in his paper "Some Thoughts on the Seventh Five Year Plan", indicated that the Eastern region consists of some provinces—e.g. West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh, and as I have mentioned earlier there have been regional disparities. It is necessary for the House and for the Planning Commission to consider this problem of regional imbalances and regional disparities from a historical point of view also. In this connection I would only like or rather I am tempted, to quote Mr. Hanumantha Rao from a historical background. That is, he says:

> "One can illustrate figures collected from the economic history of this country, particularly of this region (i.e. Eastern region) that in the whole of centuary and half before Independence the rate of taxation was very high in this region, i.e. the whole of Eastern zone. And the extraction of surplus from the rural sector was much higher whether in terms of per capita or per hectare than from many other parts of the country. Of course there had been a significant drain of resources from the country in the colonial period to countries outside".

It is not necessary for me to quote further, but therein lies the basic reason of backwardness of the Eastern region. (*Time Bell rings*) Madam, you have already warned me and therefore I shall not take much of your time, I do not like to embarrass you in the least. There has been a historical background to backwardness of the Eastern region. I hope the hon. Minister would consider this thing in depth.

I can anticipate his reply. His reply would be that attempts are being made by the Planning Commission and different Ministries for some developmental activities in this region, but he should know that the per capita transfer from the Union to this region has been always below the national average. Of course, there has been some increase in the recent years. I do not ignore that; I know facts say so. But what is the backlog because of historical reasons? If you ignore the historical reasons, which I have mentioned, of the British days then these increases in transfer from the Union to the States for this region does not eliminate or can never eliminate the backlog to which this region has been subjected to from the days of imperialist domination of our country. Now he would say that the

Gadgil formula takes care of that. Madam, may I request, according to me—I do not want to go into details—the Gadgil formula, in the matter of devolution of funds, does not take care of these historical, social problems. Therefore, my approach, my request to the Government as an economic and social activist would be, please try to revise the Gadgil formula from historical point of view and then and then alone this backwardness from these areas of the Eastern region can be eliminated and liquidated and these can be put at par with other States which have gone far-ahead. Madam, in this case the question of land reforms is there. I am very sorry to say that the Planning Commission has not mentioned, has not even fixed up the target for the 7th Five-Year Plan regarding land reforms. Lastly, I would say it has got its political implication. The Government, the ruling party and all the parties in the country should know the political implication of this imbalance. I would quote from one paper which says..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Please don't take much time.

SHRI CHITTA BASU: The meaning of that is these economic imbalances and regional disparities lead the people to discontent and this discontent makes the people loyal to the regional parties, regional organizations and regional forces. In order to stabilize the unity of the country and in order to strengthen the unity of the country it is necessary to remove the economic imbalances and regional disparities. For that purpose, I say, a historical approach has to be given and the Gadgil formula has to be revised so that the economically backward regions can overtake the backlog which have been created by the British imperialists in our country. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): The honourable Minister, please.

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : मैंने भी नाम दिया था, लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Execuse me, if we get time after the Minister's intervention you will be allowed to speak.

श्री राम नरेश कुशवाहा : अगर समय न रहे तो ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कनक मुखर्जी) : जी ठीक है । मिनिस्टर साहब के बोलने के बाद अगर टाइम रहा, तो आप बोलेंगे ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : जब सब को समय दिया है, तो मुझे ही अकेले क्यों छोड़ दिया गया है? मेरी भी बात माननीय मंत्री जी सुन लीजिए और उसके बाद आप जवाब दें ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कनक मुखर्जी) : पहले मंत्री जी बोल लें, फिर आप बोलें ।

After the Minister you can speak because up to five o'clock we have time.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI AJIT PANJA): I think if the honourable Member is the only person, let him speak, because after five o'clock this will lapse. That is the difficulty. आनरेबल मेम्बर बोल सकते हैं ।

श्री रामनरेश कुशवाहा : मुझ पर तो आप दो-पांच मिनट का बंधन लगा सकती हैं । मंत्री जी पर क्या लगायेंगी, या प्रस्तावक पर क्या लगायेंगी ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Please take only five minutes—not more than that.

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कल्पनाथ राय जी को धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश जिलों की पिछड़ेपन के लिए आयोग का प्रस्ताव किया है ।

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

हम लोग अपने क्रांतिकारी होने का अभिशाप भोग रहे हैं।' अगर आप देखेंगे, तो गौतम बुद्ध वहीं पैदा हुए थे जिन्होंने पाखंड खण्डन का बीड़ा उठाया ब्राहमणवाद का सत्यानाश कर दिया। उसी क्षेत्र में कबीर पैदा हुए थे, जायसी पैदा हुए थे, शेरशाह सूरी पैदा हुए जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी और किसी तरह दस वर्ष शासन में भी रहा। अंग्रेजों के जमाने में भी वही इलाका सबसे ज्यादा विद्रोही रहा और आजादी के बाद भी सब से पहले वही जिला चार विधायक और एक संसद् सदस्य देने वाला देवरिया जिला था। उसी इलाके में डा0 राम मनोहर लोहिया पैदा हुए, उसी इलाके में जयप्रकाश नारायण पैदा हुए जिन्होंने इस सरकार के छक्के छुड़ा दिये। इसलिए यह हम सब भोग रहे हैं। अंग्रेज के जमाने में . . . (व्यवधान) अभीअभी 1857 का जिक्र किया था मैंने, आखिरी लड़ाई 28 दिसम्बर 1857 को साहनपुर में हुई थी जो मझौली की लड़ाई के नाम से मशहूर है और उसमें हम लोगों के पुरखों ने भी हिस्सा लिया था और उनकी सारी जमीनें छीनी गईं थीं, लेकिन जिनकी जमीनें छीनी गई थीं, वह आज भी उसी तरह तबाह हैं, चौरा-चौरी का जिक्र आया, लेकिन चौरा-चौरी के फांसी पाने वालों को स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का दर्जा नहीं दिया गया। उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह माफिया गिरोह कहां है? माफिया गिरोह और नक्सलपंथी या जंगल पार्टी ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऊंची जातियों के जो अपराधी हैं उनको बचाने वाले आफिसर हैं, सरकार के लोग भी हैं, एम.एल. एज. और एम.पी. भी हैं। इसलिए वे अपराधी होते हुए भी डकैत न कहला करके माफिया गिरोह कहलाते हैं। इसके विपरीत जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, हरिजन और आदिवासी हैं उनको नक्सलाइट कह कर मार डाला जाता है, जगंल पार्टी कह कर मार डाला जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह गरीबी जो है इंदिरा जी ने भी कहा था कि अगर गरीबी नहीं मिटेगी तो खून की नदियां बह जायेंगी। अगर विषमता नहीं मिटेगी तो हिंसात्मक क्रांति हो जायेगी। यह इंदिरा जी का कहना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विद्रोही कहां पर पैदा हो रहे हैं? ये चंबल की बीहड़ों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का उत्तरी हिस्सा, तेलंगाना में पैदा होते हैं। आखिर यह विषमता जो है रिजनल इबैलैंसज की वजह से ही ये सारे विद्रोही होते हैं। नाम चाहे आप कुछ भी दीजिए। लेकिन यह सारा का सारा मामला गरीबी का मामला है और उसी से यह विद्रोह पैदा होते हैं। क्योंकि आपने समय बांध रखा है और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे विकास होगा। रेल लाइन कुछ लोग अगर उधर के थे बन गई तो बन गई। पटेल कमीशन भी है और यह कमीशन भी बनेगा। मैं जानता हूं कि कमीशन किसी भी मामले को ठंडा करने के लिए ही बनाया जाता है। जैसे मंडल कमीशन या पटेल कमीशन या उत्तर प्रदेश का तराई कमीशन। यानी कमीशन में लोग उलझे रहें तब तक आग अपने आप ठंडी हो जाए और कोई काम न हो। तो यह कमीशन जो बने ठीक है, लेकिन यह कोई बहुत फायदेमंद नहीं होगा। पटेल कमीशन भी तो बना था। पटेल कमीशन ने कहा था कि बड़ी लाइन से इस हिस्से को जोड़ देना चाहिए ताकि औद्योगिक विकास हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। बाढ़ नियंत्रण नहीं हो रहा है। कल्पनाथ राय जी से मैं कहना चाहता हूं पता नहीं उन्होंने कहा है या नहीं, आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी काट करके लालघाट के पास केवल एक किलोमीटर की दूरी पर है। अगर एक किलोमीटर की दूरी काट दी तो कल्पनाथ राय जी का घर घाघरा नदी की धारा में होगा या इस बगल में होगा या उस बगल में होगा, यह कल्पनाथ राय जी बता दें, घाघरा नदी की धारा पुरानी है और लालघाट से हो करके दो धाराएं हैं एक मऊ के पास गिरती थी और एक कालान्तर में वह फरही नाला, बहेड़ी नाला हो करके घाघरा में आ गिरती थी।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कनक मुखर्जी): आप खत्म करिए। मिनिस्टर साहब को भी बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा: मैं दे रहा हूं। मैं केवल समस्या पर ही आ रहा हूं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं। आज वह कट रही है, कोई दूसरा हल नहीं है और अगर वह कट गया तो बलिया और आजमगढ़ दोनों जिलों

में कितनी तबाही होगी इसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। देवरिया में 13 चीनी मिलें हैं। आप उद्योगों के नक्शे में देवरिया जिले को तो डाल देते हैं लेकिन लोगों को मिला क्या है? न टैक्स मिलता है, न नौकरी मिलती है और न कुछ मिलता है। गन्ना कहते हैं वह भी पूरा नहीं, औद्योगिकरण के नाम पर गोरखपुर का फर्टिलाइजर है, मंडुआ जो डीजल लोकोमोटिव है, यही तो है। पूर्वी जिले में और कुछ नहीं है। कैसे औद्योगीकरण होगा? कर्जा लेकर तो उद्योग लगाते हैं, बिजली नहीं मिलती है और उद्योग नष्ट हो जाता है। कर्जा न चुका पाने के कारण घर नीलाम करने के लिए कुर्की पहुंच जाती है। इसलिए अगर पूर्वी जिलों का विकास करना है तो आयोग तो बने वह जांच करेगा, लेकिन मेरा आयोगों में बहुत विश्वास नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि यह रीजनल इम्बेलैंसेज समाप्त करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्फरास्ट्रक्चर पैदा करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं?

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।

SHRI AJIT PANJA: Madam, I thought I would be getting some time to reply to this very informative and excellent debate which took place for several days and in which many Members took part.

I am grateful to the mover of the Resolution, Mr. Kalpnath Rai because one of the most important aspects of our entire Planning has been on various points ventilated by various Members *i.e.* what is to be done in respect of certain areas, in respect of a group of people, in respect of a class of organisation of a part of the country where along with the mainstream of development, those class of people or those tribal people or those Scheduled Castes and Scheduled Tribes or a portion of that State have not developed.

Madam, this Resolution is on a different point. It is not regarding entire UP or about the Eastern region; it is regarding Eastern UP. I would like to emphasise one point through you on the Hon. Members. Most certainly, I agree, it is the duty of the Union Government and the Planning Commission to see that the regional imbalances are taken care of and inter-State disparity is removed, but within a State, between one district and another, between one subdivision and another and between one block and another, it is for the State Government or the Union Territory concerned to look after. But for that reason, one cannot say that the Union Government or the Planning Commission has no duty to correct those imbalance. Therefore, keeping in view the position of the Eastern UP, as far back as 1962, a Commission was set up known as the Patel Commission. It made an in-depth study and gave its recommendations. Two hon. Members have said that the recommendations of the Patel Commission were not given effect to. It is not correct. it was because of the recommendations of the Patel Commission that various aspects of the development were taken care of in fifteen of the 57 districts whose geographical area is 29 per cent of the entire State and the total population covered was 32.5 per cent.

The Patel Commission has recommended ten major heads for implementation. They were: agricultural production and allied programmes, fertilisers, cooperative credit, research work on paddy, supply of improved seeds, food preservation, animal husbandry, fisheries, small-scale industries and private minor irrigation works. Implementation on all these ten heads was done. As the planners found that disparity had existed even after that, a major thrust sometimes called a booster dose with modern scientific approach was suggested to remove the disparity. Though the Patel Commission's major heads on rural development programme were not fully implemented, yet majority of its recommendations had been implemented. This was so because we found that certain defects and difficulties had arisen from the Patel Commission's recommendations. Therefore, Dr. Sen's Committee was set up in March 1983. It went into it in detail to find out why the Eastern UP was not developing while Western UP was making development. Was it the States fault or was it a because of the financial cons-

[Shri Ajit Panja]

traints or was it that somebody else was coming in the way of its development? After it submitted its report an agricultural thrust in that particular area was suggested. Immediately that was given effect to and the results were very good. Still it was found that the results were not as good as they were expected. Thereafter in 1983 a new strategy was evolved. So far as eastern Uttar Pradesh and eastern region of India were concerned, the agricultural strategy was headed by Dr. S. P. Das Gupta, Adviser. (Perspective Planning) Planning Commission. When this was done, we found it was gradually developing; and the development of eastern U. P. and the entire eastern India rests upon one pivot. that is, the fast development of agriculture. For this reason, a just comparative chart of U. P., taking into account the Sixth Plan and Seventh Plan was prepared. In the Sixth Plan agriculture got an allotment of Rs. 316.21 crores; and in the Seventh Plan it has been raised to Rs. 786.96 crores, that is, an increase of 148.9 per cent.

So far as Bihar is concerned, for agriculture, the Sixth Plan allotment was only Rs. 163.66 crores; and in the Seventh Plan it has been raised to Rs. 278.15 crores, that is, an increase of 70 per cent. I can go into the details. but I do not want to go, because time is short.

So fas as Sixth Plan is concerned, Uttar Pradesh got a total allocation of Rs. 5,850 crores. Because of the particular direction given by our Government and according to the decision of the Planning Commission to remove regional given by our Prime Minister these regional imbalances are taken care of as quickly as possible. The amount which has been alloted to U. P. in the Seventh Plan alone is Rs. 10,447 crores, that is, an increase of 78.6 per cent over the Sixth Plan.

So far as Bihar is concerned, the Sixth Plan allocation was Rs. 3,225 crores. Now in the Seventh Plan it has been increased to Rs. 5.100 crores. The percentage of increase is 58.1. Now from this figure the entire increase which I have got with me, it will be seen, Madam, that the highest increase has been made in rural development and agriculture so far as U. P. is concerned. And there the percentage of increase is 148.9 so far as agriculture in the Sixth and Seventh Plans is concerned. So far as rural development in the Sixth and Seventh Plans is concerned, the percentage of increase is 182. Madam, these figures are in respect of Uttar Pradesh.

Madam, these figures normally go to show that the points which were agitated by hon. Members are very correct. But, unfortunately, the hon. Members did not find time to look into these figures. But the Seventh Plan has taken a perfect note of all, this, not only Bihar and Uttar Pradesh but also the entire eastern region. Therefore, the entire strategy of having agricultural produce in Punjab and Haryana belt has been shifted to entire eastern region of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Assam, Tripura and some of the sister States which could produce rice and wheat, if possible, if not fruit. So far as production of fruit is concerned emphasis has been given on fruit cultivation. For the reason in order to see that fertilisers goes to the cultivators in time, a scheme has been worked out. As for the mills they get ready for the purpose of grinding wheat for making flour available to the people. So far as the FCI is concerned, they have started augmenting the entire storage capacity for eastern sector and structural facilities so that when it comes up, it will be of a great value.

Madam, the difficulty is that with all these reports when they put emphasis, we have to go side by side with the development of industries and minerals and with the development of modern things. We have to certainly look after the agriculture also. So when the Shift is on agriculture, it appears that although in Eastern U.P. the area available for rice cultivation is 68.9 per cent the actual cultivation is only on 50 per cent, which is an imbalance within. Therefore, an Adviser of the Planning Commission went to U. P. and had a specific talk with the Chief Minister so that these intra-State imbalances which have taken place could be

taken care of. Now. with the emphasis of the Seventh Plan on agriculture in the entire eastern region--where Western U.P. does not fall--this is a point to be taken note of. For taking care of these imbalances, inter-State imbalances or imbalances between east and west, or imbalances within a State like imbalances between one district and another several steps have been taken.

So far as the industrial sector is concerned, no-industry districts or districts which have no industry have been given the highest priority with the best possible incentives, so that gradually we can go down from the district. Now the cry is that we have to remove the intra-district disparities and now we have to think of sub-divisional disparities and then intra-block disparities. Therefore, Madam, I hope that the entire House will appreciate that it is a question of looking at the whole matter and having a thrust. Particular attention has been given for tribals and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is why the Tribal Sub-Plan has been made. Mr. Basu mentioned about the Gadgil Formula. The Gadgil Formula has been modified. as Mr. Basu has correctly pointed out. Therefore, first with the resources available. we pre-empt, taking into consideration where we have to put the focus in respect of various areas of development. After separating that amount, it goes as special Central assistance, as for example, in the case of West Bengal, Rs. 20 crores extra--not demanded by the State—had to go there because the Planning Commission found that the power sector in the State had to be augmented. So this amount had to be given and it has been given. In Bihar, U.P. and in southern States, where there are rice-growing areas producing good rice, we are putting a thrust so that it comes up.

Madam, I was very pained to hear one or two Members saying 'Let us divide U. P." Now if Balkanisation is thought of by some people, then I and the Government are terribly against it. The whole of India shall have to be kept intact. It is not a question of dividing everything and then administering property. If there is disparity in U. P. between the east and the west. if there is disparity in Bihar, shall we go on dividing and making our country smaller and smaller? Madam, in your knowledge you know that such Balkanisation always makes a country wholly weak.

Therefore. when all this is taken in view and as one after another, it has been taken care of by the Planning Commission and even as late as in 1984, I would certainly request the hon. Member to withdraw his Resolution. So far as Bihar is concerned, I have given the figures. So I would also request the hon. Member who moved the amendment to withdraw it

There is one small point raised by an hon. Member about the provision in the Constitution. We are very much aware of article 340 whereby a commission can be appointed. I am not going into the argument whether the Constitution-framers by mentioning "classes" referred to a particular class. I am not going into that. But the Planning Commission is fully aware of it, the Government of India is fully aware of it and from 1962 we have been consciously trying to attack the problem areas. That is. wherever there is poverty, the target is there, and it is a direct assault on these problem areas. With these words, Madam. I request the movers of the Resolution and the amendment to withdraw them.

5.00 P.M.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, डा. मनमोहन सिंह जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर की पर कैपिटा इनकम 574, देवरिया की 694, बस्ती की 563, आजमगढ़ की 645, वाराणसी की 713, बलिया की 595, गाजीपुर की 649, जौनपुर की 535, मिर्जापुर की 1000, फैजाबाद की 612, गोंडा की 604 और बहराइच की 581 है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, हिन्दुस्तान में सबसे कम पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के संबंध में विचार करें और

[श्री कल्पनाथ राय]

इसके लिए ठोस और समय-बद्ध कार्यक्रम अपनायें।

इन शब्दों के साथ, आदरणीय प्रधान मंत्री जी और योजना मंत्री जी की इच्छा है, अतः मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): First I shall put the amendment to vote. The question is—

पंक्ति एक में 'पूर्वी भाग' शब्दों के पश्चात 'तथा बिहार' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Is it the pleasure of the House to permit Shri Kalp Nath Rai to withdraw his Resolution?

(No hon. Member dissented.)

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): The House stands adjourned till 11.00 am on Monday, the 17th March 1986.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 17th March, 1986.